सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

Title Code : DELHIN28985.
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.parivahanvishesh.com

परिवहन विशेष

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

जितना अधिक आप उनमें अच्छाई देखेंगे, उतना ही आप अपने आप में अच्छा स्थापित करेंगे .

वर्ष 01, अंक 47, नई दिल्ली

मंगलवार, 02 मई 2023, मूल्य ₹ 5, पेज 8

दिल्ली परिवहन आयुक्त द्वारा वाहनों को स्क्रैप करने के लिए दिए गए दिशा निर्देश सब पर लागू या नहीं, बड़ा सवाल ?

संजय बाटला

नई दिल्ली। दिल्ली परिवहन आयुक्त के द्वारा दिल्ली को प्रदुषण मुक्त करवाने और एनजीटी/माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मानक वाहन-2 श्रेणी के समय दिए निर्देश को लागू करवाने के नाम का प्रयोग कर अपने पद की पूरी शक्ति का प्रयोग करने में व्यस्त हैं और उसके लिए ऐसे दिशा निर्देश/आदेश पारित करते जा रहे हैं जिनका मोटर वाहन नियम और भारतीय कानून में कही भी होना सम्भव नहीं पर फिर भी हो रहा है और भारतीय न्यायिक प्रणाली, प्रशासन, राज्य सरकार आंखे और मुंह बंद करके बैठे हैं। आख़िर क्यों, बड़ा सवाल ?

अब देखना यह है कि क्या

जारी दिशा निर्देश सब पर एक समान लागू किए जाते रहेंगे या इसमें भी जनता और ताकतवर जनता में फर्क दिखने में आयेगा।

दिल्ली की भोली भाली जनता इन्तजार करे दो चार दिन और फिर दिखेगा इस आदेश का पालन।

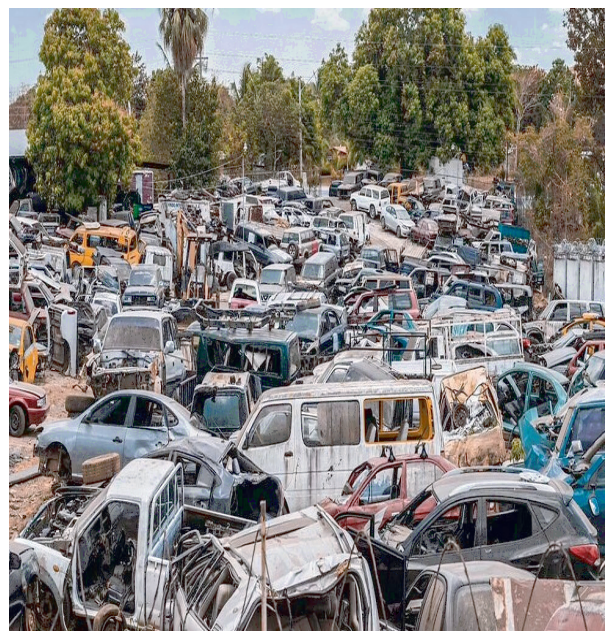

शराबी चालक ने कैब ड्राइवर को बोनट पर लटकाकर तीन किलोमीटर तक दौड़ाई कार...

राजधानी दिल्ली में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। रविवार रात करीब 11 बजे आश्रम चौक से निजामुद्दीन दरगाह की तरफ एक कार चालक ने बोनट पर लटके एक शख्स को लेकर करीब तीन किलोमीटर तक कार दौड़ाई। हालांकि समय रहते पुलिस ने शख्स को बचा लिया।

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में बीती रात करीब 11 बजे आश्रम चौक से निजामुद्दीन दरगाह की ओर आ रही एक कार के बोनट पर एक व्यक्ति को करीब 2-3 किलोमीटर तक घसीटा गया। हालांकि इस दौरान सड़क किनारे मौजूद पीसीआर वैन ने कार के बोनट पर लटके शख्स को देखकर उसका पीछा किया और कार को रुकवाया। पुलिस के अनुसार, आरोपी चालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, घटना के वक्त कार आश्रम चौक से निजामुद्दीन दरगाह की तरफ आ रही थी। पीड़ित व्यक्ति की पहचान चेतन के रूप में हुई है। चेतन ने बताया कि मैं ड्राइवर हूं, मैं एक यात्री को छोड़कर जैसे आश्रम के पास पहुंचा तो एक कार ने मेरी कार को तीन बार हिट किया, फिर मैंने इन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन ये नहीं रोके फिर मैं इनके बोनट के ऊपर लटक गया, फिर भी इन्होंने नहीं रोका।

चेतन का आरोप है कि वह मुझे आश्रम चौक से निजामुद्दीन तक घसीटता गया। रास्ते में मैंने एक पीसीआर देखा और उन्होंने हमारा पीछा किया तब जाकर ये कार रोकी। वह व्यक्ति पूरी तरह से नशे में था।

आरोपी रामचंद कुमार ने कहा कि मेरी कार उनकी कार को हिट नहीं की थी, मैं गाड़ी चला रहा था तभी वो जानबूझकर मेरी कार के बोनट पर चढ़ गए। मैंने उनसे नीचे उतरने को कहा लेकिन उन्होंने नहीं सुना। मैंने फिर अपनी कार रोका और उनसे कहा कि आप ये क्या कर रहा हो?।

advertisement Tariff
w.e.f. 1st January 2023

परिवहन विशेष
दिल्ली, एनसीआर से प्रसारित लोकप्रिय साप्ताहिक हिन्दी समाचार पत्र

in Rs. / Sq. Cm.

	Basic	3rd Page	Back Page	Front Page Semi Solus	Fornt Page Solus
Delhi Aur Delhi	BW - Colour	Colour	Colour	Colour	Colour
Delhi	100*	200*	250*	300	300

Special Instructions:-
- Innovation on any page will be accepted at a premium of 100% on applicable card rate.
- Any specified position will be accepted at a premium of 25% on applicable card rate.
- B/W advertisement on page 3/Back will charged at colour rate.
- Classified display advertisement will be charged on basic display rate.
- Pointers 4x4 sq. C. or 5x4 sq. cm. will be charged as per card rate.
- box reply charges (each box) will be charged Rs. 150/-
- Political advertisement - as applicable.

परिवहन विशेष में विज्ञापन के लिए ऑनलाईन भुगतान सीधे बैंक खाते/फ़ोन पे पर कर सकते हैं और विज्ञापन के मैटर के साथ ऑनलाईन भुगतान की रसीद व्हाट्सऐप नंबर 09212122095 या newstransportvishesh@gmail.com पर भेज सकते है। भुगतान करने के लिए *NEFT / IMPS / RTGS*
Account Name:-Transport Vishesh Limited
IFSC CODE :- INDB0001396
Cur Account no :- 259212122095
या Phone pay :- 9212122095

डीटीसी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर यूनियन द्वारा शांतिपूर्ण बाइक रैली सफल हुई

परिवहन विशेष संवाददाता

नई दिल्ली। डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन आप का सभी मिडिया साथियों का ध्यान इस और दिलाना चाहती है की डीटीसी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की आज बाइक रैली बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हो गई, यह रैली डीटीसी हेड क्वार्टर इंदरप्रस्थ के सामने से -TMS रूट से चली और वहीं आकर खत्म की गई, और रैली का रूट इस प्रकार था आई टी ओ, राजघाट, आईएसबीटी, पुरानी विधानसभा, मॉडल टाउन, आजाद पुर, वजीरपुर डिपो, पंजाबी बाग, मायापुरी चौंक, धौला कुआं, मेडिकल, लाजपत नगर, सराय काले खां, आईपी, डीटीसी हेड क्वार्टर इंद्रप्रस्थ पर रैली आकर रूकी और फिर रैली को डीटीसी हेड क्वार्टर पर संबोधित किया, यह विशाल बाइक रैली लगभग 52 किलोमीटर की थी और इस रैली को 5 घंटे का सफर तय कर के वापस डीटीसी हेड क्वार्टर पहुंची, यूनियन के प्रतिनिधि मंडल IAS श्रीमती शिल्पा शिंदे महोदया जी से मिले और इन मांगों पर पूरी होने का विश्वास दिलाया है और कहां की जो मेरे दायरे में जो मांगें है वो मांगें जल्द पूरी होने का आश्वासन दिया है और आगे भविष्य में यूनियन को ज्यादा समय और विस्तार से समय देने का भी आश्वाशन दिया, यूनियन द्वारा दिया गया ज्ञापन पत्र पर अगर विभाग द्वारा कोई भी मांग पूरी नहीं होती तो, यूनियन फिर एक महिने बाद विशाल आन्दोलन करेगी, और मांगें पूरी न होने पर यह आन्दोलन की प्रक्रिया इसी तरह चलती रहेगी, औरइन मांगों को लेकर बाइक रैली का आयोजन किया गया था,(1) दिल्ली परिवहन निगम में डीटीसी की खुद की बसें तुरंत लाई जाए,(2) डीटीसी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की नौकरी तुरंत पर्मानेंट पक्की की जाए, और तब तक नौकरी पर्मानेंट नही होती तब तक समान काम का समान वेतन लागू किया जाए,(3) डीटीसी के बेड़े में जो भी बसें आ रही है उन बसों में डीटीसी ड्राइवर को डीटीसी के PAY ROLL पर प्राथमिकता सबसे पहले दी जाए,(4) डीटीसी में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को 8 घंटे की नौकरी व समान काम का समान वेतन और न्यूनतम वेतन तुरंत लागू किया जाए,(5) चेंज ओवर सिस्टम तुरंत बंद किया जाए, कर्मचारियों की ड्युटी डिपो टू डिपो तुरंत की जाए,(6) डीटीसी कर्मचारियों का ट्रांसफर उस कर्मचारी के पते एड्रेस के हिसाब से 10 किलोमीटर के दायरे में तुरंत करने का प्रावधान बनाया जाए, ताकि ट्रांसफर करने के नाम पर से भ्रष्टाचार जो चरम सीमा पर है उसे खत्म किया जाए,(7) दिल्ली परिवहन निगम की खुद की बसें इंटरस्टेट अंतर्राजिय स्तर पर तुरंत चलाने का प्रावधान बनाया जाए, (8) डीटीसी व क्लस्टर बसों में से किलोमीटर स्कीम खत्म की जाए, ताकि दिल्ली की जनता सुरक्षित रह सके।

निवेदक डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन
अध्यक्ष= ललित चौधरीमहामंत्री= मनोज शर्मा

टैंपल'स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/ एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण रजिस्टर्ड

कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063, कॉरपोरेट

कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

रियायत समाप्त कर रेलवे ने 2242 करोड़ रुपये कमाए, RTI के तहत दिया ये जवाब

मध्य प्रदेश के चंद्र शेखर गौड़ की ओर से दायर सूचना के अधिकार (आरटीआई) के जवाब में रेलवे ने कहा कि एक अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच उसने लगभग आठ करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को रियायतें नहीं दीं, जिनमें लगभग 4.6 करोड़ पुरुष, 3.3 करोड़ महिलाएं और 18,000 ट्रांसजेंडर शामिल थे।

नई दिल्ली। रेलवे ने वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली रियायत को रद्द कर 2022-23 में उनसे करीब 2,242 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया है। देश के सबसे बड़े ट्रांसपोर्टर ने 20 मार्च 2020 से जब कोरोना संकट के कारण वरिष्ठों को दी जाने वाली रियायत को स्थगित किया था से 31 मार्च 2022 के बीच 1500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी की थी।

रेलवे ने आरटीआई के जवाब में बताया- आठ करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को नहीं मिली रियायत

मध्य प्रदेश के चंद्र शेखर गौड़ की ओर से दायर सूचना के अधिकार (आरटीआई) के जवाब में रेलवे ने कहा कि एक अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच उसने लगभग आठ करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को रियायतें नहीं दीं, जिनमें लगभग 4.6 करोड़ पुरुष, 3.3 करोड़ महिलाएं और 18,000 ट्रांसजेंडर शामिल थे। आरटीआई के जवाब के अनुसार, इस अवधि के दौरान वरिष्ठ नागरिक यात्रियों से कुल 5,062 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्त हुआ है। जिसमें रियायत के निलंबन के कारण अर्जित अतिरिक्त 2,242 करोड़ रुपये शामिल हैं।

जनसभा का संचालन जीबी पंत पैरामैडिकल टेक्निकल एंप्लॉयज यूनियन के अध्यक्ष भारत वीर , महासचिव सुशील कुमार ने किया।

मई दिवस पर पंत अस्पताल में कर्मचारियों ने भरी हुंकार, गेट मीटिंग कर सैंकडों स्टाफ ने विरोध जताया

एस ठी सेठी

नई दिल्ली, परिवहन विशेष। अन्तरराष्ट्रीय मजदूर दिवस पर दिल्ली के सरकारी, अर्द्ध सरकारी ,प्राइवेट क्षेत्र से जुडे लाखों मेहनतकशों ने निजीकरण को बढावा देने वाली नीतियों,के खिलाफ और बेरोजगारी के बढते सैलाब से गुस्साए कामगारों ने अपने-अपने संस्थानों के गेट पर,और खुले में हजारों की संख्या में मौजूद लोगों की जनसभाओं को उनके नेताओं ने संबोधित किया। हालांकि आज सोमवार को सुबह से ही रूक-रूक कर तेज बरसात ने भी कहर बरपाने की कोशिश की। लेकिन ,कामगारों का मजदूर दिवस पर जोश ठंडा होने की बजाए उबाल लेता दिखाई दिया।

दिल्ली सरकार और केन्द्र सरकार के करीब पांच दर्जन अस्पतालों के स्वास्थ्य कर्मचारियों की यूनियनों (.नेशनल पब्लिक हेल्थ एलाईंस) से जुडे सैंकडों कर्मचारियों ने अपने यूनियन नेताओ के नेतृत्व में पंत अस्पताल परिसर गेट में हर वर्ग से जुडे हैल्थ वर्कर्स ने दिल्ली सरकार द्वारा तमाम लैब जांच को निजी हाथों में दिए जाने के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। हैल्थ कर्मचारियों ने बाजूओं में काली पट्टियां बांधकर विरोध जताया। हाथों में

आउटसोर्सिंग व पीपीपी आदि तरीकों से जनस्वास्थ्य सेवा के निजीकरण को बंद करो, असें से अनुबंधित मजदूरों को तुरंत नियमित करो।

वहीं सालाना रिन्यूअल की हरैस्मेंट भरी प्रक्रिया खत्म करो, एनआरएस रद्द करके सभी डिमांडिंग बेनिफिट आधारित ओपीएस प्रदान किया जाए। जैसे नारे लिखी हुई तख्तियां सभी ने हाथों में पकडी हुई थी। कर्मचारी खासकर दमनकारी नीतियों के खिलाफ लैब सर्विस सहित अस्पताल के अन्य सेवाओं को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के नाम पर छंटनी की तलवार लटकाने से खासे गुस्से में है। नेशनल पब्लिक हैल्थ एलाईंस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि 6 अप्रैल को तमाम मांगो को लेकर उपराज्यपाल को 10 सूत्रीय डिमांड लेटर दिया है। डिमांड में मरीजों और जनता के हित के मद्देनजर हैल्थ क्षेत्र का बजट 10 % करने की मांग की है। नये अस्पतालों को नई तकनीकी और सुविधाओं से लैस किया जाना चाहिये। डीएसएसबी के द्वारा खाली पडे ढेरों पदों को भरने की.कारवाई की जानी चाहिये। जरूरत के मद्देनजर ही स्टाफ भर्ती होने चाहिये। वहीं सालों से सेवा दे रहे संविधान कर्मियों को पक्का किया जाना चाहिये। कर्मचारियों को कैशलेस सुविधाएं दी जानी चाहिये जो नही दी जा रही है।

जनसभा का संचालन जीबी पंत पैरामैडिकल टेक्निकल एंप्लॉयज यूनियन के अध्यक्ष भारत वीर, महासचिव सुशील कुमार,ने किया।अध्यक्षता, एनपीएचए) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार, ने की। इसके अलावा मुकेश कुमार, विकास,किशौर राणा,सत्येन्द्र मिश्रा,एसडी सिंह,रविंद्र, रामप्रवेश, दिनेश मिश्रा, और पुष्पा सहित अस्पताल के बडी संख्या में टेक्निकल, नोन टेक्निकल, जनरल स्टाफ भी मौजूद रहे। वहींऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर(एआईयूटीयूसी) के सचिव मंडल सदस्य रमेश ने बतौर मुख्य वक्ता के कहा कि सरकार मजदूर विरोधी , कर्मचारी विरोधी,जन विरोधी,उदारीकरण, निजीकरण, निगमीकरण, आउटसोर्सिंग, पब्लिक प्राइवेट, पार्टनरशिप को लागू करते हुए श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी संशोधन कर रही है।स्थाई रोजगार को खत्म कर अप्रैंरटिसशिप एक्ट में बदलाव किया गया है। पेंशन समाप्त कर ,फिक्स्ड टर्म एंम्पलॉयमेंट को लाया जा रहा है।

सार्वजनिक उधोगो को बेचने व जनकल्याण कारी सेवाएं जैसेशिक्षा,इलाज,बिजली, ,पानी,रेलवे परिवहन,को मुनाफाखोरों, पूंजीपतियों के हवाले किये जाने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की दमनकारी ,मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ एकताबध होकर विरोध जताना ही मई दिवस के शहीदों को सच्ची श्रद्धांजली होगी।

इनसाइड

प्रेग नेंसी में मोबाइल रेडिएशन से दूरी बनाना जरूरी वरना शिशु को हो सकता है मेंटल प्रॉब्लम

अगर गर्भवती महिला के आसपास अत्यधिक मोबाइल रेडिएशन है, तो उसके पेट में पल रहे बच्चे के मानसिक विकास पर बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है. यही नहीं, बच्चे को जीवन भर बिहेवियर प्रॉब्लम से गुजरना पड़ सकता है. जानें, प्रेग्नेंसी के दौरान मोबाइल रेडिएशन से अजन्मे बच्चे के विकास में क्या समस्या आ सकती है और इससे कैसे बचा जा सकता है. हम सभी सुनते आए हैं कि अधिक मोबाइल फोन का इस्तेमाल हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाता है. खासतौर पर प्रेग्नेंट महिला और उसके पेट मे पल रहे बच्चे के लिए ये और भी खतरनाक हो सकता है. प्रेग्नेंसी के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल से पेट में पल रहे बच्चे के विकास पर बुरा असर पड़ता है और इसकी वजह से प्रीमेच्योर डिलीवरी तक हो सकती है. केवल मां ही नहीं, अगर मां के आस पास लोग वायरलेस चीजों का अधिक इस्तेमाल कर रहे है तो इसका भी भ्रूण में पल रहे बच्चे पर खराब असर पड़ सकता है. मॉमजंक्शनमें छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, येल स्कूल ऑफ मेडिसिन में किए गए शोध में पाया गया है कि अत्यधिक मोबाइल रेडिएशन में अगर गर्भवती मां रहती है तो जन्म के बाद बच्चे को जीवन भर बिहेवियर प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है. यही नहीं, इसकी वजह से गर्भ में पल रहे बच्चे के मानसिक विकास पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है. तो आइए जानते हैं कि प्रेग्नेंसी के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल से बच्चे को क्या नुकसान हो सकता है और हम इससे कैसे बच सकते हैं.

वायरलेस डिवाइस कैसे करता है प्रभावित

दरअसल जब हम मोबाइल, लैपटॉप या किसी भी तरह के वाइफाई या वायरलेस डिवाइस के संपर्क में आते हैं तो इससे हर वक्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स निकलते रहते हैं. ये वेव्स हमारे शरीर के डीएनए को डैमेज करने की क्षमता रखते हैं और हमारे शरीर में बन रहे जीवित सेल्स के मोलक्यूल्स को बदल सकते हैं. जिसका असर लॉग टर्म काफी खतरनाक हो सकता है. चूंकि भ्रूण हर वक्त ग्रोथ कर रहा है ऐसे में उसके डीएनए और लीविंग सेल्स आसानी से इसकी चपेट में आ सकते हैं. जिसका दूरगामी असर भी काफी खतरनाक हो सकता है.

क्या कहता है शोध

अलग अलग शोधों में पाया गया कि मोबाइल के इस्तेमाल से बच्चे पर कोई खास असर नहीं पड़ता लेकिन अगर मां और बच्चा 24 घंटे मोबाइल रेडिएशन के बीच हैं तो बच्चे की मेमोरी, ब्रेन ग्रोथ और बिहेवियर में खतरनाक रूप से समस्या आ सकती है. शोधों में यह भी पाया किया गया कि प्री और पोस्ट डिलीवरी के बाद ऐसे बच्चों में हाइपरटेंशन की समस्या हो जाती है जो समय के साथ बढ़ती जाती है. यही नहीं, बच्चे की भाषा, संचार पर भी इसका बुरा असर पड़ता है.

इस तरह करें बचाव

- घर में जहां तक हो सके वाई फाई या ब्लूटूथ उपकरणों का इस्तेमाल कम करें.
- बेहतर होगा अगर आप मोबाइल की बजाय लैंड लाइन फोन का इस्तेमाल करें.
- रेडियो, माइक्रोवेव, एक्सरे मशीन आदि से दूरी बनाएं.
- मोबाइल टावर आदि के आस पास घर ना लें.

गर्भावस्था में मोबाइल के नुकसान

-गर्भवती महिलाओं में रेडिएशन से मस्तिष्क की गतिविधि पर भी प्रभाव पड़ सकता है जिससे थकान, चिंता और नींद में रुकावट पैदा होती है.
-गर्भावस्था के दौरान रेडियो वेव्स के लगातार संपर्क से आगे जाकर कैंसर का खतरा बन सकता है.
-मां गर्भावस्था के दौरान फोन का अधिक इस्तेमाल करे या काफी करीबी लोग घर पर इसका इस्तेमाल करें तो बच्चे के व्यवहार में 50 प्रतिशत बदलाव देखने को मिलता है.

-ऐसे बच्चे अधिक एग्रेसिव और हाइपरटेंशन के पेशेंट हो जाते हैं.

8 सेफ्टी टिप्स हैं महिलाओं के लिए बेहद जरूरी, घर से अकेले निकलने पर करें फॉलो, खुद कर सकेंगी अपनी सुरक्षा

सड़क पर पैदल चलते समय हमेशा ट्रैफिक के अपोजिट डायरेक्शन में चलें.
कैब या ऑटो में बैठते समय गाड़ी का नम्बर किसी करीबी को मैसेज करें.
अकेले बाहर निकलने से पहले जरूरी सेफ्टी टूल्स को पर्स में रखना ना भूलें.

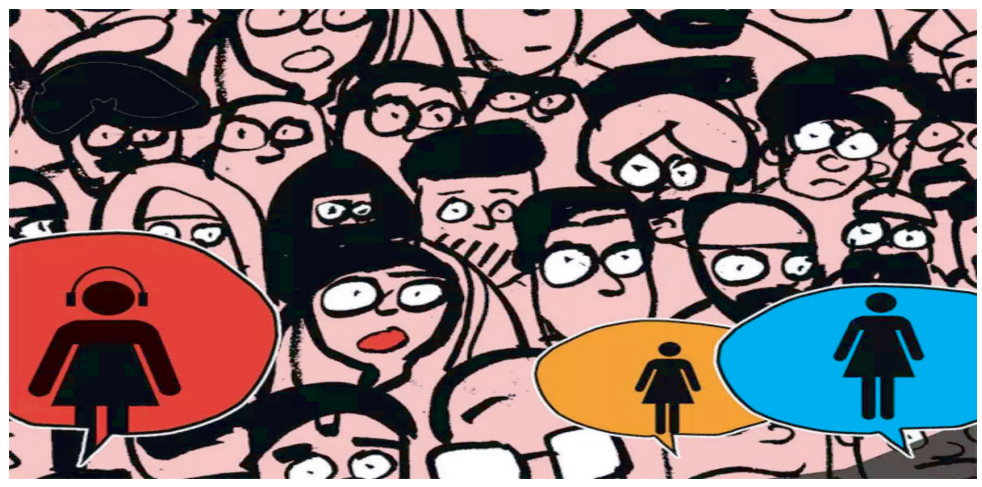

ज्यादातर जगहों पर महिलाओं का घर से अकेले निकलना सेफ नहीं होता है. ऐसे में महिलाएं अक्सर अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित नजर आती हैं. खासकर शाम के समय महिलाओं के खिलाफ होने वाली घटनाएं काफी बढ़ जाती हैं. ऐसे में अगर आप घर से अकेले निकल रही हैं तो कुछ बातों का खास ख्याल रखकर आप अपनी सुरक्षा आसानी से पुख्ता कर सकती हैं.
घर से अकेले बाहर जाते समय महिलाएं कई बार डरी सहमी महसूस करती हैं. हालांकि, ऐसे में कुछ सेफ्टी टिप्स फॉलो करके आप अपनी सुरक्षा खुद सुनिश्चित कर सकती हैं. आइए जानते हैं महिलाओं से जुड़े कुछ जरूरी सेफ्टी टिप्स के बारे में.

बेस्ट बडी के साथ रहें

अकेले घर से बाहर रहने के दौरान आप अपने भाई, बहन, पिता, पति या दोस्त जैसे किसी बेस्ट बडी को फोन कॉल कर सकती हैं. ऐसे में उन्हें अपने घर पहुंचने का समय और ऑटो या कैब का नम्बर बताकर आप खुद को सेफ रख सकती हैं.

सड़क पर रहें सेफ

अकेले होने पर सड़क के किनारे पैदल चलते समय हमेशा ट्रैफिक के अपोसिट डायरेक्शन में चलें. जिससे ट्रैफिक आपको सामने से आता हुआ दिखाई देगा और पीछे से हमला होने का डर कम रहेगा. वहीं बैग या पर्स को सड़क की बजाए दीवार की तरफ रखें. इसके अलावा किसी के पीछा करने पर आसपास मौजूद घर की कॉल बेल बजाकर मदद मांगे.

सुरक्षा के साथ करें सवारी

कैब बुक करते समय टैक्सी स्टैंड या टैक्सी सर्विस की मदद लें. वहीं ऑटो भी हमेशा प्री पेड बूथ से ही बुक करें. इससे आपके अलावा दूसरों को भी टैक्सी या आटो की जानकारी रहेगी. साथ ही अकेले सफर करते समय खाली बस में बिल्कुल ना चढ़ें.

रास्तों पर रहें सतर्क

अकेले सफर करते समय सूनसान रास्तों से ना गुजरें. ऐसे में जाने पहचाने और भीड़ भाड़ वालों रास्तों पर चलना बेस्ट रहता है. साथ ही रात के समय अंधेरे रास्तों को भी अवॉयड करें और रोशनी वाले मार्ग पर ही सफर करें.

खुद को रखें तैयार

अकेले सफर के दौरान असुरक्षा महसूस होने पर फौरन ऑटो या कैब का नम्बर किसी करीबी को मैसेज करें. इसके अलावा आप गूगल मैप पर आसपास के पुलिस स्टेशन और पीसीआर की लोकेशन भी चेक कर सकती हैं. साथ ही घर के किसी सदस्य या पुलिस चौकी का नम्बर स्पीड डायल में रखें और जरूरत पड़ने पर तुरंत उस नम्बर पर कॉल करें.

पार्टी में बरतें सावधानी

पार्टी में अकेले शिरकत करने के दौरान अंजान लोगों से पर्याप्त दूरी बनाकर रखें. इसके अलावा आसपास के लोगों पर भी नजर रखें और पार्टी में नशीली चीजों का सेवन भूलकर भी ना करें.

ड्राइव करने के टिप्स

अगर आप घर से बाहर अकेले ड्राइव कर रही हैं तो गाड़ी के सभी शीशों और दरवाजों को लॉक कर दें. इसके अलावा म्यूजिक या फोन कॉल में बिजी होने से बचें. इससे आप मुसीबत के दौरान तुरंत सतर्क हो सकती हैं. वहीं रात के समय गाड़ी को बेसमेंट में पार्क ना करें और गाड़ी के पास पहुंच कर पर्स से चाबी निकालने की बाजए चाबी को पहले से हाथ में रखें.

कम पढ़ी-लिखी महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं ये ऐप्स

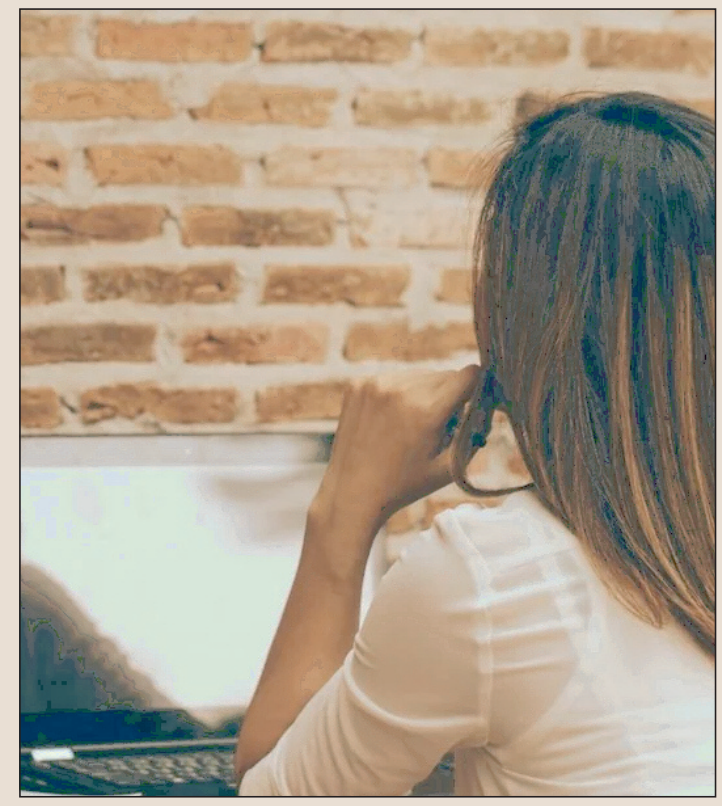

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में इंटरनेट टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हुई है.

दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, हैदराबाद, पुणे और अन्य मेट्रो सिटीज़ में ऐप्स की मदद से आगे बढ़ रही हैं और पैसे भी कमा पा रही हैं. सबसे खास बात यह है कुछ प्लेटफॉर्म्स पर महिलाओं को नौकरी के लिए बहुत ज्यादा फॉर्मल तरीका नहीं अपनाना पड़ता, जिससे उनकी झिझक कम हो जाती है.
अगर आप किसी कारणवश अपनी डिग्री पूरी नहीं कर पाई हैं, या आपने केवल 10वीं या 12वीं तक की ही पढ़ाई की है और आप अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं, इस अब आपको ऐसा मौका मिल सकता है. क्योंकि देश में कई ऐसे मोबाइल ऐप बनाए गए हैं, जो खासरकर महिलाओं को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं. इन ऐप्स के इस्तेमाल से महिलाओं ने 2021 में तरक्की के कई रास्ते खोले और अब 2022 में भी ये उनकी मदद कर रहे हैं. दिल्ली-एनसीआर (**Delhi-NCR**), मुंबई, हैदराबाद, पुणे और अन्य मेट्रो सिटीज में बहुचर्चित 'अपना (**apna**)' ऐप ने महिलाओं के बीच अच्छी पकड़ बनाई है. बीते साल करीब लाखों महिलाओं ने इसका इस्तेमाल कर नौकरी पाई. सबसे खास बात यह है कि इस प्लेटफॉर्म पर महिलाओं को नौकरी के लिए बहुत ज्यादा फॉर्मल तरीका नहीं अपनाना पड़ता, जिससे उनकी झिझक कम हो जाती है.
इन ऐप्स पर सिर्फ अपनी जानकारी डालने के बाद उनके पास जरूरत के हिसाब से नौकरी पाने के ऑफर आते रहते हैं. 12वीं पास महिलाओं ने सबसे ज्यादा टेलीकॉलर, बीपीओ, बैक ऑफिस, रिसेप्शनिस्ट, फ्रंट ऑफिस, टीचर, अकाउंटेंट, एडमिन ऑफिस असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी के लिए आवेदन किया है.

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का मजबूत प्लेटफॉर्म

इसी तरह खास महिलाओं के लिए चलाई जा रही सोशल नेटवर्किंग साइट 'शीरोज (**Sheroes**)' भी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में एक मजबूत प्लेटफॉर्म के रूप में सामने आई है. यहां हर उम्र वर्ग की महिलाएं, ऐप या वेबसाइट के माध्यम से जुड़ती हैं. वह नौकरी के अवसर भी तलाशती है, साथ ही अगर वह अपने लेवल पर किसी तरह का बिजनेस कर रही हैं, तो उसे प्रमोट भी करती हैं. बिजनेस वुमेन इसके सहारे अपना नेटवर्क मजबूत कर रही हैं. इस तरह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मोबाइल और इंटरनेट टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हुई.

बिज़ी लाइफ में इन तरीकों से महिलाएं निकालें खुद के लिए समय

महिलाओं को खुद के लिए समय निकालना बहुत कठिन टस्क हो गया है. महिलाओं को खुद के लिए समय निकालना बहुत कठिन टस्क हो गया है.

कामकाजी महिलाओं (Working Women) के ऊपर घर के साथ-साथ ऑफिस की भी जिम्मेदारी होती है. ऐसे में कुछ तरीकों की मदद से वे अपना काम आसान कर सकती हैं और अपने लिए समय बचा सकती हैं ताकि वे अपनी सेहत का भी ध्यान रख सकें.

आजकल के बिजी लाइफस्टाइल में खुद के लिए समय निकालना बहुत कठिन टास्क हो गया है. इस समस्या से सबसे अधिक महिलाएं प्रभावित हैं और जो महिलाएं वर्किंग हैं उनके लिए तो खुद के लिए समय निकालना नामुमकिन है. वर्किंग विमेन (Working Women) के ऊपर घर के साथ-साथ ऑफिस की भी जिम्मेदारी होती है. जिसे पूरा करते-करते वे ना तो चैन की सांस ले पाती हैं और ना ही अपनी नींद पूरी कर पाती हैं. ऐसे में स्वास्थ्य पर काफी गहरा असर पड़ता है.
इस समस्या को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज के इस आर्टिकल में हम कुछ ऐसे हैक्स बताने जा रहे हैं जो आपके बहुत काम आ सकते हैं.

चाबियों पर लगाएं अलग-अलग रंग की नेल पॉलिश

अक्सर जब किसी काम को जल्दी पूरा करना हो या हम जब जल्दी में होते हैं तभी छोटी-छोटी चीजों की वजह से देर होने लगती. ऐसे में आप अपने घर की कई चाबियों को अलग-अलग रंग की नेल पॉलिश से रंग सकते हैं. इससे आपको पर्टिकुलर लॉक के लिए सारी चाबी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इससे आप अपने समय की बचत कर सकते हैं.

कंघी करते समय रखें ध्यान

ऑफिस जाते समय जल्दी-जल्दी में बालों को सुलझाने में महिलाएं बालों के साथ खींचतान करने लगते हैं. जिससे बाल अधिक टूटते हैं और नीचे गिर कर काम बढ़ा देते हैं. इससे बचने के लिए अपने हेयर ब्रश में बटर पेपर लगाकर कंघी करें. इससे बाल जल्दी सुलझ जाएंगे और नीचे भी नहीं गिरेंगे.

हेयर स्ट्रेटनर से प्रेस करें

सुबह के समय जल्दी रहे तो आप प्रेस के लिए हेयर स्ट्रेटनर का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे आपके कपड़े जल्दी प्लेस होंगे और आपका समय बच जाएगा.

जो महिलाएं मां नहीं बन पातीं, उनमें हार्ट फेल होने का खतरा ज्यादा: नई रिसर्च

महिला को अगर गर्भवती होने के दौरान दिक्कतें आएं या मेनोपॉज के दौरान परेशानियों का सामना करना पड़े तो बाद के सालों में उसे दिल की बीमारी होने का रिस्क बढ़ जाता है.

महिलाओं के प्रजनन इतिहास का उन्हें होने वाली दिल की बीमारी से संबंध होता है. (सांकेतिक तस्वीर) महिलाओं के प्रजनन इतिहास का उन्हें होने वाली दिल की बीमारी से संबंध होता है.

ब्रिटेन में हुई रिसर्च से पता चला है कि जिन औरतों में बांझपन (infertility) की समस्या होती है, उनका हार्ट फेल होने की आशंका 16 फीसदी तक ज्यादा होती है. महिला को गर्भवती होने के दौरान दिक्कतें आएं या मेनोपॉज़ में परेशानी हो तो बाद के सालों में दिल की बीमारी का रिस्क बढ़ जाता है.
प्रेग्नेंसी के दौरान विटामिन A की कमी हो सकती है खतरनाक, जानें यह क्यों जरूरी
प्रेग्नेंसी के दौरान विटामिन A की कमी हो सकती है खतरनाक, जानें यह क्यों जरूरी
लंदन: एक नए शोध से पता चला है कि महिलाओं में बच्चे पैदा न कर पाने (infertility) की समस्या का संबंध दिल की बीमारी से भी होता है. ब्रिटेन में हुई रिसर्च के बाद दावा किया गया है कि जिन औरतों में बांझपन यानी इनफर्टिलिटी (infertility) की समस्या होती है, उनका हार्ट फेल होने की आशंका बाकी महिलाओं से 16 फीसदी तक ज्यादा होती है.
अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी जर्नल में छपे इस शोध में कहा गया है कि महिलाओं के प्रजनन इतिहास से काफी हद तक पता चल जाता है कि उन्हें भविष्य में दिल की बीमारी होने का कितना खतरा है. महिला को अगर गर्भवती होने के दौरान दिक्कतें आएं या मेनोपॉज़ के दौरान परेशानियों का सामना करना पड़े तो बाद के सालों में उसे दिल की बीमारी होने का रिस्क बढ़ जाता है. इस शोध के दौरान दो तरह के हृदयाघात यानी हार्ट फेल होने की स्टडी की गई. पहला preserved ejection fraction के साथ हार्ट अटैक (HFpEF) जिसमें दिल की मांसपेशियां खून पंप करने के बाद पूरी तरह फैल नहीं पातीं. दूसरा हार्ट फेल्योर विद reduced ejection fraction (HFrEF). इसमें बाएं वेंट्रीकल यानी दिल के निचले भाग के कोष से हर धड़कन के बाद जितना खून शरीर में जाना चाहिए, वो नहीं जा पाता. महिलाओं में हार्ट फेल के ज्यादातर मामले HFpEF के ही होते हैं. शोध करने वाली टीम की लीडर और मैसाचूसेट्स जनरल हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. एमिली लाउ ने बताया कि रिसर्च के दौरान ये पता लगाने की कोशिश की गई कि महिलाओं में थायरायड या जल्दी मेनॉपॉज़ जैसी समस्याओं का भी क्या प्रजनन क्षमता और दिल की बीमारी से कोई लेना-देना होता है या नहीं. लेकिन इस धारणा को लेकर किसी तरह के पुख्ता सबूत अभी नहीं मिल पाए हैं.
शोधकर्ताओं का कहना है कि अभी तक ये तो पता था कि जिन महिलाओं में बच्चे पैदा न कर पाने की समस्या होती है, उनमें हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी होने के चांस ज्यादा होते हैं.
लेकिन बांझपन का दिल की बीमारी पर असर को लेकर कोई पुख्ता स्टडी नहीं हुई थी. आमतौर पर दिल की बीमारी को 50 साल के बाद की समस्या माना जाता है, जबकि बांझपन उम्र के 20वें, 30वें या 40वें पड़ाव पर आने वाली दिक्कत है. इसलिए इन दोनों के संबंध पर गौर नहीं किया जाता. अब महिलाओं में बच्चे पैदा न कर पाने की क्षमता का कुछ नहीं किया जा सकता लेकिन भविष्य का ध्यान तो रखा ही जा सकता है ताकि उन्हें दिल की बीमारियों से बचाया जा सके.

अभी दो दिन और बरसेंगे बदरा, मई में हो रहा फरवरी सा अहसास; मौसम विभाग ने बताया क्या है वजह

मंगलवार को हल्की होगी और बुधवार को तेज बारिश का अनुमान है। अभी गर्मी से एक हफ्ते तक तो राहत रहेगी।

नई दिल्ली। पश्चिम विक्षोभ के असर ने दिल्ली-एनसीआर के मौसम को पूरी तरह से बदल दिया है। सोमवार को दिल्ली-एनसीआर में दिन में ही अंधेरा छा गया और उसके बाद हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हुई। बारिश ने पारे को सामान्य से 13 डिग्री तक लुढ़का दिया। इस कारण से मौसम ने मई में फरवरी जैसे मौसम का अहसास कराया। वहीं शाम साढ़े पांच बजे तक 14.8 मिमी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में भी अच्छी बारिश होने की संभावना जताई है।

मौसम का मिजाज तो रविवार से ही बदला हुआ था लेकिन एक मई को नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से सोमवार को ठंडी-ठंडी हवा के साथ हुई बारिश ने तापमान को काफी गिरा दिया।

अधिकतम तापमान सामान्य से 13 डिग्री कम 26.1 डिग्री व न्यूनतम तापमान सामान्य से पांच डिग्री कम 19.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इससे पहले रविवार को हुई बारिश ने तापमान को सामान्य से दस डिग्री तक गिरा दिया था। इस कारण से तापमान 28.7 डिग्री दर्ज हुआ। इससे पहले 2021 में 19 अप्रैल को अधिकतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था।

वहीं बारिश की बात करें तो शाम साढ़े पांच बजे तक औसतन 14.8 मिमी बारिश दर्ज की गई। रिज में सबसे अधिक 21.2 व सफदरजंग में 13.8 मिमी बारिश दर्ज की गई। एक मार्च से अब तक दिल्ली में 74.5 मिमी बारिश दर्ज की गई है। बीते साल 31 मई को 17.8 मिमी बारिश दर्ज की गई थी।

एक-दो दिन में न्यूनतम तापमान और गिर सकता है और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के उपमहानिदेशक डॉ. कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि जब भी पश्चिमी विक्षोभ असरदार होते हैं तो ऐसा मौसम बन जाता है। अभी लगातार दो विक्षोभ की सक्रियता रही है इस कारण से तापमान में इतनी गिरावट दर्ज हुई है। अभी दो से तीन दिन बारिश होती रहेगी।

मंगलवार को हल्की होगी और बुधवार को तेज बारिश का अनुमान है। अभी गर्मी से एक हफ्ते तक तो राहत रहेगी। अगले सप्ताह से तापमान बढ़ने का अनुमान है।

इनसाइड

दिल्ली-यूपी पुलिस ने एनकाउंटर के बाद भगोड़े 'गोलीबाज' बदमाश को मेरठ से दबोचा, साथी भाग निकला

नई दिल्ली। दिल्ली के आदर्श नगर में युवक सोनू दूबे को गोली मारकर भाग रहे बदमाश रंजीत झा उर्फ गांजा को मेरठ अपराध नियंत्रण पुलिस और दिल्ली की स्पेशल सेल ने रविवार देर रात सुबेपुर गांव के पास मुठभेड़ में गिरफ्तार लिया। उसके पैर में गोली लगी है। दिल्ली के मुकंदपुर पार्ट वन निवासी रंजीत झा सुपारी लेकर हत्या करने वाला बदमाश है। वह मनोज की हत्या के मामले में वांछित था। उस पर अन्य कई केस भी दर्ज हैं। रंजीत का एक साथी बाबू फरार हो गया। उसकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने मौके से 9 एमएम की पिस्टल और बाइक बरामद की है।

पुलिस के मुताबिक रविवार दोपहर इस बदमाश ने आदर्श नगर निवासी सोनू दुबे पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। इसके बाद वह बाइक लेकर गाजियाबाद की ओर फरार हो गया। उसकी लोकेशन के आधार पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम के इंस्पेक्टर शिवकुमार और एसआई अनिल ढाका टीम के साथ पीछा कर रहे थे। उन्होंने कंकरखेड़ा थाने के सुबेपुर गाव के पास आकर आरोपी की घेराबंदी की। आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस की ओर से फायरिंग की गई। पैर में गोली लगने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक रंजीत थाना बुराड़ी के एक हत्याकांड में भी वांछित था। इसमें मनोज की हत्या की गई थी। इस मामले में आरोपी मुकेश उर्फ बोना को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन दो शूटर फरार हो गए थे। जांच में पता चला था कि वर्ष 2020 में मुकेश के दो साथियों अनुज और आनंद की हत्या राजा ने पांच शूटरों से कराई थी। इस पर मुकेश बोना ने राजा को मारने के लिए रंजीत और गौरव से संपर्क किया था।

यमुना को प्रदूषण मुक्त कराने के लिए आंदोलन में शामिल होगा पंचायत संघ, 96 गांव की खाप का फैसला

नई दिल्ली। राजधानी के गांवों की समस्याओं का समाधान नहीं होने और यमुना को प्रदूषण मुक्त नहीं करने के विरोध में रविवार को लाडो सराय में 96 गांवों की खाप की पंचायत हुई। पंचायत में ग्रामीणों ने एक स्वर में कहा कि यमुना की सफाई के लिए चार जून को यमुना संसद संगठन के मानव श्रृंखला बनाने के कार्यक्रम में वह शिरकत करेंगे।

पंचायत की अध्यक्षता लाडो सराय 96 खाप के प्रधान चौ. नरेश ने की। उन्होंने कहा कि यमुना की सफाई के लिए उनकी खाप ने कमर कस ली है और खाप के अधीन आने वाले समस्त गांवों के निवासी यमुना की सफाई के लिए आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पंचायत में दिल्ली पंचायत संघ दिल्ली प्रदेश के प्रमुख थान सिंह यादव ने गांवों की 18 सूत्री मांगों के संबंध में ग्रामीणों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की कोई सुध नहीं ले रहा है और और ग्रामीणों पर उन्हें परेशान करने वाले नियम थोपे जा रहे हैं। इस कारण इन 18 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन की तैयारी की जा रही है।

चौ. नरेश ने 18 सूत्री मांगों को ग्रामीणों का कवच करार दिया। उन्होंने कहा कि गांवों को हाउस टैक्स, पार्किंग चार्ज आदि टैक्स, सीलिंग, भवन उप नियम आदि से राहत देने और ग्रामीणों को मालिकाना देने की आवश्यकता है। पंचायत में बिहारी वेलफेयर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय के अलावा जेकेबीएम के अध्यक्ष राजेश सेजवाल, साईं जन विकास फाउंडेशन के अध्यक्ष बीबी मिश्रा भी उपस्थित थे।

एलजी ने यमुना कायाकल्प परियोजना का किया निरीक्षण

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने रविवार को सिग्नेचर ब्रिज से आईटीओ के बीच यमुना कायाकल्प परियोजना के तहत किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष के तौर पर परियोजना के पहले चरण का निरीक्षण कर उन्होंने मौजूदा हालात की समीक्षा की।

मुख्यमंत्री आवास पर भाजपा का बेमियादी धरना शुरू, सरकार की घेराबंदी की पूरी तैयारी

प्रदेश भाजपा मुख्यमंत्री निवास के करीब अनिश्चितकालीन धरना देगी। इस धरना कार्यक्रम के संयोजक प्रदेश महामंत्री हर्ष मल्होत्रा करेंगे। सोमवार को चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र की जनता के साथ भाजपा सांसद डॉ. हर्षवर्धन धरने पर बैठेंगे।

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री निवास के सौंदर्यीकरण मामले को लेकर भाजपा ने पूरी तरह से दिल्ली सरकार की घेराबंदी करने की नीति तैयार की है। प्रदेश भाजपा मुख्यमंत्री निवास के करीब अनिश्चितकालीन धरना देगी। इस धरना कार्यक्रम के संयोजक प्रदेश महामंत्री हर्ष मल्होत्रा करेंगे। सोमवार को चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र की जनता के साथ भाजपा सांसद डॉ. हर्षवर्धन धरने पर बैठेंगे।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली सरकार भ्रष्ट है, जो केवल अपने नेताओं की स्वार्थ सिद्धि व वोट बैंक की नीति पर काम करती है। शिक्षा क्रांति की बात की तो वहां स्कूल रूम घोटाला किया, सार्वजनिक परिवहन की बात कही तो मेट्रो के चौथे फेज को लंबित किया एवं बस खरीद घोटाला किया, स्वास्थ्य की बात की तो कोविड काल तक में घोटाले किए। मोहल्ला क्लीनिक जैसा छलावा दिया।

इसी तरह फ्री बिजली-पानी की बात की तो सब्सिडी घोटाला किया एवं दिल्ली जल बोर्ड को दिवालिया किया और इन सबसे ऊपर शराब घोटाला एवं हवाला घोटाले तो ऐसे किए कि आज दो प्रमुख मंत्री जेल में हैं। इतने घोटाले करके भी मुख्यमंत्री का मन नहीं भरा और उन्होंने अपने राज महल रूपी बंगले को लेकर भी घोटाला कर दिया।

छोटी-छोटी बातों से अवसाद का शिकार हो रहे दिल्लीवाले, टेली मानस से रोज 50 मरीजों की दूर की जा रही समस्या

नई दिल्ली। घर में परेशानी, पत्नी से झगड़ा, दफ्तर में साथ काम करने वालों से मनमुटाव जैसे छोटे-छोटे कारणों से दिल्ली वाले अवसाद का शिकार हो रहे हैं। कई लोग मानसिक समस्या से परेशान होकर गलत कदम तक उठा लेते हैं। ऐसे लोगों की मानसिक समस्याओं को दूर करने के लिए मानव व्यवहार और संबद्ध विज्ञान संस्थान (इहबास) ने केंद्रीय कार्यक्रम के तहत टेली मानस की शुरुआत की है।

मानसिक समस्या से जूझ रहे लोग 14416 और 1800914416 हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इस हेल्पलाइन पर हर दिन 50 के करीब कॉल आ रही हैं। कॉल करने वाले अधिकतर लोग 20 से 40 की उम्र के हैं।

इन कॉल करने वाले लोगों से खराब मूड, नींद में खलल, मनोवैज्ञानिक समस्याएं, तनाव, पारिवारिक समस्या, निराशा, कुछ न होना लगना, आशा खो देना, आक्रामकता, नशा करना, इच्छा का खत्म होना, आत्महत्या का ख्याल आना, अजीब आवाज सुनाई देना, बहुत ज्यादा खुशी, मेडिकल समस्या, परीक्षा संबंधी समस्या, अधिक काम करना, थकान, अजीब और विचित्र आवाज सुनना, घबराहट होना, आवाज सुनाई देना , खुद को नुकसान पहुंचाना, कोई समस्या होना, दवा संबंधित दिक्कत, शरीर में अतिरिक्त परेशानी, दुर्घटना के पीड़ित और स्कूल जाने से इन्कार करने सहित 27 लक्षणों पर बात की जाती है।

टेलीमानस से रोज 50 मरीजों की दूर की जा रहीं समस्याएं

इहबास के उप चिकित्सा अधीक्षक व प्रोफेसर मनोचिकित्सा विभाग के डॉ. ओम प्रकाश ने कहा कि मनोरोग से जूझ रहे लोगों की समस्या काउंसलिंग करके दूर की जा सकती है। हम टेलीमानस के माध्यम से रोज 50 मरीजों की समस्या दूर करते हैं। इस दौरान परिवार का भी साथ लेते हैं। कॉलर की अधिकतर समस्याएं ऐसी हैं जिन्हें बात करके दूर किया जा सकता है। यह ऐसी समस्याएं हैं जो वास्तव में कुछ हैं ही नहीं, लेकिन दूरी के कारण विकराल हो

जाती हैं। उन्होंने कहा कि मरीज से बात करने के दौरान यदि हमें लगता है कि मामला ज्यादा गंभीर है तो मरीज को अस्पताल बुलाया जाता है और दवा दी जाती है। हालांकि ज्यादातर मामले फोन पर ही डॉक्टर से बात करवाकर दूर हो जाते हैं।

भेजा जाता है डॉक्टर के पास

फोन पर बात करने के दौरान यदि कॉलर को लगता है कि व्यक्ति ज्यादा परेशान है और काउंसलिंग से बात नहीं बन सकती तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास भेजा जाता है। इस दौरान उसके आसपास के क्षेत्र के डॉक्टर का नाम व पता भी मरीज को बताया जाता है। ऐसे मरीजों को तुरंत दवा लेने की जरूरत पड़ती है जिससे न्यूरो संबंधी दिक्कत को दूर किया जा सके। डॉक्टरों का कहना है कि मानसिक रोग के लिए दवा से ज्यादा काउंसलिंग महत्वपूर्ण है लेकिन कई बार दवा के बिना काम नहीं चल पाता।

युवाओं में आ रही ज्यादा दिक्कत

परिवार में झगड़े, काम का दबाव, आपसी उलझन सहित अन्य समस्याओं में सबसे ज्यादा 20 से 40 वर्ष के युवा फंस रहे हैं। इहबास में आने वाली कॉल में सबसे ज्यादा कॉल इसी आयु वर्ग की होती है। इहबास के कॉल सेंटर पर 24 घंटे सातों दिन सुविधा उपलब्ध रहती है। ऐसे में सबसे ज्यादा कॉल रविवार व शनिवार को आती हैं। मरीज कई बार कॉलर से बात करने के बाद कॉल डॉक्टर के पास ट्रांसफर करवाता है। बता दें कि कॉलर आपकी समस्या सुनते हैं और 27 सवालों के आधार पर स्थिति का आकलन कर फोन को डॉक्टर के पास भेज देते हैं।

ली जाती है परिवार की मदद

अवसाद में पहुंच चुके लोगों की मदद के लिए डॉक्टरों के साथ परिवार की भी मदद ली जाती है।

अधिकतर लोग पढ़े-लिखे न होने से दलालों के चंगुल में फंस गए और खून पसीने की कमाई देकर जमीन खरीद ली।

दलालों के चंगुल में फंसकर जीवनभर की कमाई गंवा दी, सैकड़ों परिवारों की आंखों में दिखा घर टूटने का दर्द

परिवहन विशेष न्यूज

घर टूटने का दर्द सैकड़ों परिवारों की आंखों में साफतौर से देखा जा सकता था। बुलडोजर घर ढहाते रहे और लोग ईंट-पत्थरों के बीच से अपना सामान निकालते रहे। लोगों ने बताया कि पुरातत्व विभाग ने जब से इनके घरों पर नोटिस चिपकाया, उनकी नींद गायब हो गई।

नई दिल्ली। दलालों के चंगुल में फंसकर सैकड़ों परिवारों ने जीवनभर की कमाई और घर दोनों गंवा दिए। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने जनवरी में किले की जमीन पर बसी बंगाली बस्ती (छुरिया मोहल्ला) की 1248 पक्के ढांचे वाली झुग्गियों पर खाली करने का नोटिस चिपकाया था। इसके बाद कई परिवार घर खाली कर चले गए थे, जबकि भारी संख्या में लोगों ने बुलडोजर और पुलिस बल देखकर सामान समेटना शुरू किया।

प्रशासन ने इन लोगों को घर खाली करने का समय दिया। आननफानन में लोग जरूरी सामान निकालकर ले जा पाए। कई परिवार आखिरी वक्त तक घर नहीं खाली करने पर अड़े रहे, उन्हें पुलिस बलों ने समझाकर किसी तरह जगह खाली करवाई। कई महिलाएं घर से निकलने के लिए तैयार नहीं थीं, महिला पुलिस ने इन्हें हटाया। एक सिरे से झुग्गियां को तोड़ने की कार्रवाई लगातार शाम तक चलती रही। भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के अलावा आरएएफ की कई कंपनियां मौके पर तैनात की गई थीं। फायर ब्रिगेड व एंबुलेंस सेवा भी तैनात की गई थी।

पांच दलालों ने मिलकर फंसाया

घर टूटने का दर्द सैकड़ों परिवारों की आंखों में साफतौर से देखा जा सकता था। बुलडोजर घर ढहाते रहे और लोग ईंट-पत्थरों के बीच से अपना सामान निकालते रहे। लोगों ने बताया कि पुरातत्व विभाग ने जब से इनके घरों पर नोटिस चिपकाया, उनकी नींद गायब हो गई। अब कहां जाकर रहेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पांच दलालों ने उन्हें फंसाया। अधिकतर लोग पढ़े-लिखे न होने से दलालों के चंगुल में फंस गए और खून पसीने की कमाई देकर जमीन खरीद ली।

कोर्ट ने चार सप्ताह के भीतर कब्जे हटाने का दिया था आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने केस की सुनवाई के दौरान 24 अप्रैल को एएसआई की खिंचाई की थी और कहा था कि वह ऐतिहासिक तुगलकाबाद किले में अतिक्रमण के मुद्दे पर मूकदर्शक नहीं बन सकता। कोर्ट ने हर हाल में चार सप्ताह के भीतर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। एएसआई ने कोर्ट को बताया था कि उसने जनवरी में किले की जमीन पर बनीं 1248 झुग्गियों पर नोटिस चिपकाए हैं, लेकिन अन्य एजेंसियों को जैसे कि दिल्ली पुलिस, निगम, डीडीए के सहयोग के बिना अवैध निर्माण को हटाने में सक्षम नहीं है। इस पर पीठ ने दिल्ली पुलिस के साथ एमसीडी और स्थानीय एसडीएम से कहा था कि वे अतिक्रमण हटाने में एएसआई को आवश्यक सहयोग प्रदान करें। इसके बाद रविवार को ये कार्रवाई की गई।

सालों तक यह मामला ठंडे बस्ते में पड़ा रहा

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को 1995 में दिल्ली विकास प्राधिकरण से तुगलकाबाद किले की 2661 बीघा जमीन रखरखाव के लिए दी गई थी, लेकिन 25 सालों में तुगलकाबाद किले की करीब 1500 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा हो गया था। वर्ष 2001 में किले की जमीन को अवैध तरीके से कब्जा किए जाने की जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। कई सालों तक यह मामला ठंडे बस्ते में पड़ा रहा, लेकिन 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और मामले को हाईकोर्ट के पास भेजकर मॉनिटरिंग करने का आदेश दिया। इस केस की सुनवाई तब से लगातार चल रही थी।

7-8 हजार रुपये प्रति वर्ग गज में खरीदी जमीन

लोगों ने 7-8 हजार रुपये प्रति वर्ग फुट में दलालों से जमीन खरीदी। अधिकतर मजदूरी करने वाले लोगों ने किस्तों में पैसे भरे। कई अब तक पैसे भर रहे थे और इस तरह से 10-15 सालों में करीब एक किमी के दायरे में हजारों झुग्गियां बन गईं। लोगों ने बताया कि सुबह उनके मकान तोड़ने के लिए जब बुलडोजर आए तो भी दलालों ने कहा वे चिंता न करें, कुछ नहीं होगा। भड़काने की कोशिश की कि सब बुलडोजर के सामने पत्थर लेकर खड़े हो जाना पुलिस लौट जाएगी, लेकिन भारी संख्या में पुलिस बल देखकर लोगों की पत्थर उठाने की हिम्मत नहीं हुई।

सवारी बैठाने पर ऑटो चालक से मारपीट व जान से मारने की धमकी

परिवहन विशेष संवाददाता

गुरुग्राम। पालम विहार थाना क्षेत्र में ऑटो में सवारी बैठाने पर ऑटो चालक से मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस को दी शिकायत में शंकर विहार कालोनी निवासी राम अवतार ने कहा कि वह सीएनजी ऑटो चलाकर अपनी गुजर बसर करता है। वह 27 अप्रैल को सवारी के इंतजार में रेजांगला चौक पर खड़ा था। इसी बीच एक सवारी उसके ऑटो में बैठ गई। ऐसे में शंकर विहार निवासी सुनील आया और ऑटो को बंद कर दिया। सुनील ने उस पर हमला बोल दिया, जिसमें उसके दांत टूट गए। जब वहां लोग एकत्रित हुए तो सुनील ने उससे कहा कि आइंदा से ऑटो में सवारी बैठाई तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी।

अवैध कब्जा हटाने के लिए 10 मई को पुलिस बल मांगा

गुरुग्राम। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने सरकारी जमीन पर एक भाजपा नेता द्वारा किए गए कब्जे को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्राधिकरण ने 10 मई को कब्जा हटाने के लिए जिला प्रशासन ने पुलिस बल की मांग की है। साथ ही ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी उपलब्ध कराने के लिए कहा है।

इस मामले में शिकायतकर्ता एडवोकेट दिनेश यादव ने प्राधिकरण के साथ-साथ गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, नगर निगम, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग को शिकायत दी थी। इसमें आरोप लगाया था कि भाजपा नेता मनीष यादव ने गोल्फ कोर्स रोड, सिंकदरपुर घोषी स्थित खसरा नंबर 352 में सरकारी जमीन पर बड़ी दुकान के अलावा छोटी दुकान और स्टाल का निर्माण भी किया है। शिकायत में कहा गया कि इससे लाखों रुपये का किराया वसूल किया जा रहा है। जबकि विभाग को लाखों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है। शिकायत मिलने के बाद प्राधिकरण के संपदा अधिकारी द्वितीय जितेंद्र गर्ग ने उपायुक्त निशांत कुमार यादव को पत्र लिखकर 10 मई को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ-साथ आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराने को कहा है।

गस्त कर रहे पुलिसकर्मियों पर फेंका पत्थर, कांस्टेबल घायल

***मसूरी।** ढबारसी गांव में शनिवार रात गस्त कर रहे कांस्टेबल पर किसी व्यक्ति ने पत्थर फेंक दिया। सिर में पत्थर लगने से कांस्टेबल घायल हो गया। कांस्टेबल का निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस अज्ञात हमलावरों पर रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है। कांस्टेबल भारत कुमार व अंकित कुमार रात 11:30 बजे नाहल पुलिस चौकी क्षेत्र के मोहल्ला मटुवा ग्राम ढबारसी में गश्त कर रहे थे। तभी किसी व्यक्ति ने उन पर पत्थर फेंक दिया।*

पत्थर कांस्टेबल भारत कुमार के सिर पर आकर लगा। दोनों सिपाही जमीन पर गिर गए। कांस्टेबल अंकित ने मामले की जानकारी थाने को दी। वहां पहुंचे अधिकारियों ने भारत कुमार को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डासना भेजा। हालत गंभीर देखकर बेहतर उपचार के लिए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। कांस्टेबल भारत कुमार की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। एसीपी निमिष पाटिल का कहना है कि कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मोहल्ला मटुवा ग्राम ढबारसी में कुछ दिन पूर्व दो पक्षों में झगड़ा हुआ था। कांस्टेबल भारत कुमार ने नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया था। संभवतः कार्रवाई से नाराज आरोपी पक्ष ने पुलिस पर पत्थर फेंका है। मामले में जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी।

भाई के जन्मदिन का सामान लेने बाजार गई छात्रा से लूटी सोने की चेन

परिवहन विशेष संवाददाता

वसुंधरा। सेक्टर-2बी में बाइक सवार दो लुटेरों ने शनिवार दोपहर बाजार से छोटे भाई के लिए जन्मदिन का सामान खरीदने गई छात्रा के गले से सोने की चेन लूट ली। छात्रा और उसकी मां ने लुटेरों को पकड़ने के लिए शोर मचाया लेकिन लुटेरे तेजी से फरार हो गए। इंदिरापुरम कोतवाली में लूट का मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही है। लुटेरे उसमें कैद हुए हैं। सेक्टर-3 में गार्डेनिया ग्लैमर फेज एक निवासी संयोगिता आहूजा परिवार के साथ रहती हैं। उनकी बेटी पास के निजी स्कूल में 12वीं कक्षा की छात्रा है। वह शनिवार दोपहर करीब दो बजे बेटी के साथ बेटे के जन्मदिन का सामान खरीदने गई थीं। उन्होंने बताया कि सेक्टर-2बी में पुलिस चेकपोस्ट के पास वह किसी से बात कर रही थीं कि पीछे से बाइक पर आए दो लुटेरों ने बेटी के गले पर झपट्टा मारकर एक तोले की सोने की चेन लूट ली। उन्होंने कहा कि चेन उनके गले में भी थी, लेकिन बाल खुले होने के कारण लुटेरे उनकी चेन नहीं देख पाए थे। गले पर झपट्टा लगते ही उन्होंने तुरंत शोर मचाया लेकिन किसी राहगीर ने मदद नहीं की। लुटेरे भागते हुए घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। लुटेरे काले रंग की स्पलैंडर बाइक पर आए थे। बाइक पर पीछे बैठे लुटेरे ने काली टीशर्ट-जींस पहनी थी।

कौशांबी में 40 हजार रुपये और चेन लूटने वालों का नहीं मिला सुराग :

27 अप्रैल को कौशांबी थाने के पास संगीता चौधरी से 40 हजार रुपये की लूट और डेढ़ घंटे बाद भोवापुर में सिद्धार्थ भारवाह से सोने की चेन लूटने की घटना में अभी तक पुलिस लुटेरों की सुराग पता नहीं लगा पाई है। पुलिस महज सीसीटीवी फुटेज खंगालने की बात कह रही है।

डीसीपी ट्रांस हिंडन जोन विवेक चंद्र का कहना है कि लुटेरों की पहचान के लिए सीसीटीवी देख रहे हैं। कैमरे में कैद लुटेरे की पहचान कर टीम रिकॉर्ड देख रही है। जल्द कोई सुराग मिलने पर लुटेरों को पकड़ा जाएगा।

बुजुर्ग की शर्मनाक हरकत: आते-जाते छात्राओं का पीछा और कसता था अश्लील फब्तियां, शिकायत के बाद आरोपी गिरफ्तार

घटना के बारे में लड़कियों ने पिता को बताया। पिता ने दो दिन तक छात्राओं के स्कूल जाने के दौरान पीछे-पीछे चलकर आरोपी पर नजर रखी और मौका पाकर उसे बीच रास्ते में दबोच लिया।

गाजियाबाद। गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र में रहने वाली दो छात्राओं से छेड़छाड़ और परेशान करने वाले बुजुर्ग श्रमिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। छात्राओं ने पिता से उसकी शिकायत की। पिता ने दो दिन तक आरोपी पर निगरानी में रखी और मौका पाकर उसे दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया। परेशान छात्राओं ने स्कूल नहीं जाने कर चेतावनी दी थी। पुलिस ने आरोपी को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया।

परिजनों ने बताया कि बड़ी बेटी 17 साल और दूसरी बेटी 11 साल की हैं। दोनों साथ दिल्ली के स्कूल पढ़ने के लिए जाती हैं। आरोप है कि नोएडा की एक सोसायटी में नौकरी करने वाला 55 साल का दयानंद दोनों छात्राओं का रोजाना पीछा कर अश्लील फब्तियां कसता था। डर की वजह से दोनों छात्राओं ने कई बार तेजी से भागकर खुद को सुरक्षित किया।

घटना के बारे में उन्होंने पिता को बताया। पिता ने दो दिन तक छात्राओं के स्कूल जाने के दौरान पीछे-पीछे चलकर आरोपी पर नजर रखी और मौका पाकर उसे बीच रास्ते में दबोच लिया। बाद में पिता ने आरोपी बुजुर्ग को खोड़ा पुलिस के सुपुर्द कर दिया। खोड़ा थाना प्रभारी योगेंद्र मलिक का कहना है कि छात्राओं के पिता ने दयानंद नाम के आरोपी के खिलाफ मुकदमा कराया था। पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

कालेज गई छात्रा अचानक हुई लापता:

साहिबाबाद कोतवाली क्षेत्र के एक कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा शनिवार सुबह अचानक रास्ते से लापता हो गई। वह कॉलेज पढ़ने के लिए जा रही थी। उसका मोबाइल घर पर ही मिला है। मां ने पुलिस को छात्रा के अगवा होने का मुकदमा कराया है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

पुलिस ने पकड़ी सीबीएसई की नकली किताबें, दो गिरफ्तार

मोदीनगर। पुलिस ने एक व्यापारी की सूचना पर नगर में दो स्थानों पर छापा मारकर सीबीएसई के पाठ्यक्रम की नकली किताबें बरामद की। पुलिस ने गैरकानूनी रूप से किताबें बेच रहें दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 161 किताबें बरामद की हैं। शिवपुरी कॉलोनी निवासी अनुज गोयल किताबों का व्यापार करते हैं। राज चौपले पर केशव ट्रेडर्स के नाम से उनकी फर्म है। अनुज ने बताया कि दिल्ली के दरियागंज स्थित पब्लिकेशन कोलोफोन लर्निंग सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड की कक्षा एक से आठ तक की किताबों की बिक्री का अनुबंध किया हुआ है। पब्लिकेशन के अनुबंध के अनुसार अनुज की फर्म के अलावा किसी अन्य को किताबें सप्लाई नहीं करता। अनुज को जानकारी मिली कि बाजार में किताबें काम दामों पर बेची जा रही है। अनुज ने फर्जीवाड़ा कर किताबें बेचने वाले दुकानदारों को चिन्हित कर पब्लिकेशन के अधिकारियों और पुलिस से मामले की शिकायत की। एसीपी रितेश त्रिपाठी ने बताया कि दिल्ली-मेरठ मार्ग पर पीबीएएस इंटर कॉलेज के समीप स्थित सुमित बुक डिपो और संतपुरा कॉलोनी में हितेंद्र जैन बुक डिपो पर छापा मारा। दोनों स्थानों से पब्लिकेशन की कुल 161 किताबें जब्त की। मामले में सुमित अग्रवाल और हितेंद्र जैन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।

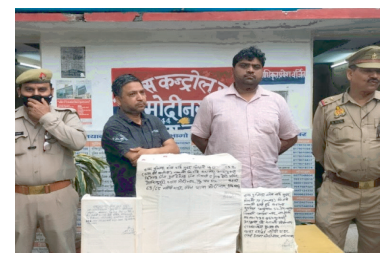

नौकरी के झांसे में फंसी युवती ने गंवाए आठ लाख रुपये

खोड़ा। थाना क्षेत्र की एक युवती ने ठग द्वारा दिए गए ऑनलाइन नौकरी के झांसे में फंसकर आठ लाख रुपये की रकम गंवा दी। टास्क पूरा करने पर युवती ने रुपये मांगे तो ठग ने फोन बंद कर दिया। युवती ने साइबर सेल को शिकायत देकर खोड़ा पुलिस को ठगी का मुकदमा कराया है। साइबर सेल ट्रांजेक्शन के आधार पर खातों की जांच कर रही है। युवती ने साइबर सेल और पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसके व्हाट्सएप पर मेसेज आया था, जिसमें ठग ने उसे पार्ट टाइम ऑनलाइन नौकरी में टास्क पूरा कर मोटी रकम मुनाफे के साथ कमाने का झांसा दिया। सबसे पहले ठग ने उसे फोन पर बात करके ग्रुप में जोड़ा और फिर अलग-अलग तरह के टास्क बताकर योजना बताई। युवती को सबसे पहले दो टास्क पूरा करने पर 300 रुपये मुनाफे दिए। तीसरी बार में एक हजार रुपये और फिर चौथी बार में 1400 रुपये दिए। इसके बाद ठग ने उनसे मोटी रकम लगाने के लिए कहा। वह ठग के झांसे में फंस गई और ज्यादा रुपये लगाने शुरू कर दिए। कई बार टास्क पूरे करने पर जब युवती ने ठग से अपना मुनाफा मांगा तो उसे रुपये ट्रांसफर करने के एवज में रुपये मांग लिए। आरोप है कि ठग ने उससे अलग-अलग खातों में 22 बार ट्रांजेक्शन करके आठ लाख आठ हजार रुपये ठग लिए। खोड़ा थाना प्रभारी योगेंद्र मलिक का कहना है कि शिकायत के आधार पर ठगी का मुकदमा दर्ज हुआ है। जांच जारी है।

राजनगर में 1358 उपभोक्ताओं को 2000 यूनिट तक बढ़ाकर भेजा बिल

गाजियाबाद। राजनगर की पॉश कालोनियों के उपभोक्ताओं के साथ मीटर रीडरों ने बड़ा खेल किया है। तीन महीने में 1358 उपभोक्ताओं की शिकायत के बाद बिलों की जांच में 300 से 2000 यूनिट तक का अंतर पाया गया है। राजनगर उपकेंद्र के उपखंड अधिकारी एनएन पटेल ने अधिशासी अभियंता को पत्र भेजकर बिलो की गड़बड़ी के बारे में अवगत कराया है। मुख्य अभियंता नीरज स्वरूप ने मामले की जांच कराकर कार्रवाई के निर्देश दिए। मीटर रीडरों द्वारा की जा रही गड़बड़ियों से उपभोक्ता ही नहीं बल्कि ऊर्जा निगम के अधिकारी भी परेशान है। हर महीने हजारों की संख्या में लोग अपने बिजली के बिल ठीक कराने बिजलीघरों पर पहुंच रहे है। उपभोक्ताओं के बिलों में 300 से 2000 यूनिटों तक का अंतर आ रहा है। राजनगर उपकेंद्र पर रीडिंग गड़बड़ी के सबसे ज्यादा मामले आ रहे है। ऊर्जा निगम ने बिजली उपभोक्ताओं के घर जाकर वास्तविक रीडिंग के आधार पर बिल जारी कराने के लिए क्यूविश कंपनी के साथ अनुबंध किया है। इस कंपनी के

मीटर रीडर घरों में जाकर लोगों के मीटरों में यूनिट के हिसाब से बिल तैयार कर भेज रहे है, लेकिन कुछ मीटर रीडर मौके पर जाए बिना उपभोक्ताओं के पास बिल भेज रहे हैं। सबसे ज्यादा उपभोक्ता राजनगर उपकेंद्र में बिल ठीक कराने के लिए पहुंच रहे हैं, जबकि इतनी ही शिकायतों का निस्तारण उपखंड अधिकारी संज्ञान लेकर कर रहे हैं। एसडीओ एसएन पटेल का कहना है उपकेंद्र पर रोजाना 100 से अधिक शिकायतें मीटर रीडिंग से संबंधित आ रही है। इनमें से अधिकांश शिकायतें आरडीसी, गोविंदपुरम, मधुबन बापूधाम, संजयनगर से आ रही हैं। वहां के लोग बिजली विभाग के अधिकारियों से मीटर रीडरों द्वारा अंदाजे से बिल बनाने का आरोप लगा रहे हैं। इसके अलावा कविनगर,शास्त्रीनगर, इलेक्ट्रो स्टील, पटेलनगर, राजेंद्रनगर इलाकों में भी बिजली बिल में गड़बड़ियों की शिकायत आ रहीं है।

कंपनी के कर्मचारियों द्वारा घर-घर जाकर रीडिंग ली जा रही है। बिना रीडिंग लिए बिल भेजने की बात निराधार है। यदि कहीं ऐसा पाया जाता है तो कंपनी द्वारा संबंधित मीटर रीडर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

- सचिन कुमार, सुपरवाइजर, क्यूविश कंपनी

मीटर रीडर के द्वारा गलत बिल भेजे जाने की शिकायतें मिल रहीं है। संबंधित कंपनी के अधिकारियों को इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

- नीरज स्वरूप, मुख्य अभियंता

उपकेंद्र शिकायतें

राजनगर 1358
कविनगर 450
इलेक्ट्रो स्टील 500
शास्त्रीनगर 300
पटेलनगर 300
राजेंद्रनगर 150

किया की गाड़ियों में हुए कई अपडेट, अब कितना बदल जाएगा आपका ड्राइविंग एक्सपीरिएंस

किआ ने अपने 2023 लाइन-अप को RDE-कंप्लेंट अनुरूप पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ अपडेट किया है। बाद वाले को 6-स्पीड मैनुअल के साथ पेश किया जाता था जिसे तीनों मॉडलों में 6-स्पीड iMT से बदल दिया गया है।

किआ ने अपनी इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन (iMT) पेशकशों से संबंधित बड़े बदलाव किए हैं। क्लचलेस मैनुअल गियरबॉक्स अब Kia Seltos, Sonet और Carens के सभी डीजल वेरिएंट में स्टैंडर्ड रूप से दिया जाएगा। यह 1 अप्रैल2023 से टर्बो-पेट्रोल वेरिएंट पर भी उपलब्ध है। RDE- कंप्लेंट 2023 Kia Seltos, Sonet और Carens को अब स्टैंडर्ड के तौर पर 6iMT वेरिएंट में अपग्रेड किया जाएगा।

किआ ने अपने 2023 लाइन-अप को RDE- कंप्लेंट अनुरूप पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ अपडेट किया है। बाद वाले को 6-स्पीड मैनुअल के साथ पेश किया जाता था, जिसे तीनों मॉडलों में 6-स्पीड iMT से बदल दिया गया है।

कितनी होगी कीमतें?

KIA Diesel iMT वेरिएंट की कीमतें सॉनेट के लिए 9.95 लाख रुपये, सेल्टोस के लिए 12.39 लाख रुपये और कॉरेंस के लिए 12.65 लाख रुपये से शुरू होती हैं।

KIA टर्बो इंजन वेरिएंट

6-स्पीड iMT किआ के अपडेटेड टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ भी उपलब्ध है। सॉनेट 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ आता है, जबकि कॉरेंस को 1.5-लीटर T-Gdi यूनिट मिलती है। टर्बो-पेट्रोल iMT वेरिएंट की कीमत क्रमशः 10.49 लाख रुपये और 12.00 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।

Carens को पांच ट्रिम्स में लिया जा सकता है, जिसमें प्रीमियम, प्रेस्टीज, प्रेस्टीज प्लस, लक्ज़री और लक्ज़री प्लस शामिल हैं। वहीं, सीटींग कपैसिटी के रूप में इसमें छह और सात सीटर विकल्प मिलता है। इस कार में 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन, 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन और 1.5-लीटर डीजल इंजन का विकल्प मिलता है।

Kia seltos Facelift

किआ सेल्टॉस अपने नए अपडेट अवतार में लॉन्च होने के लिए तैयार है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो कंपनी इस फेसलिफ्ट कार को 2023 के मध्य में लॉन्च कर सकती है। सेल्टोस फेसलिफ्ट की पहले मिली जानकारी के मुताबिक, इस कार को एक बिल्कुल फ्रेश लुक दिया गया है। यह कार एक अपडेटेड हेडलैंप यूनिट और नए LED डीआरएल के साथ आएगी। साथ ही इसे एक नया फ्रंट फेसिया भी मिलेगा। फीचर्स लिस्ट में नई फ्रंट ग्रिल, बड़े एयर-डैम, नई LED टेल लैंप और पीछे की तरफ बंपर भी देखने को मिलेगा।

इनसाइड

डीजल इंजन के साथ Toyota Innova Crysta की भारतीय बाजार में वापसी, जानिए कीमत और फीचर्स

भारत में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली MPV ने फिर से वापसी कर ली है। हम बात कर रहे हैं डीजल इंजन वाली Toyota Innova Crysta के बारे में। क्या हैं इसके नए दाम और फीचर्स जान लीजिए।

नई दिल्ली। भारतीय कार बाजार में डीजल इंजन वाली Toyota Innova Crysta की फिर से वापसी हो गई है। हाल ही में कंपनी ने इसे नई कीमत के साथ लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे नए आरडीई नियमों के साथ पेश किया है। क्या कुछ मिलेगा नई डीजल इंजन वाली Toyota Innova Crysta में, आइए जान लेते हैं।

डिजाइन में बदलाव

Toyota Innova Crysta डीजल के एक्सटीरियर में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। कंपनी ने शानदार बोनट, क्रोम से घिरी एक बड़ी ट्रेपोजॉइडल ग्रिल, ब्लैक-आउट चिन के साथ बंपर और स्लीक हेडलाइट्स को इसके फ्रंट में ऑफर किया है। कार की साइड में ब्लैक-आउट बी-पिलर्स, इलेक्ट्रिकली-फोल्डिंग ओआरवीएम, ब्लैक क्लैडिंग के साथ व्हील-आर्क और 16 इंच डायमंड कट अलॉय व्हील दिया है।

मिल गया नया डीजल इंजन

बाजार में Innova Crysta पहले से हाइब्रिड और पेट्रोल इंजन के साथ उपलब्ध थी। इसके डीजल इंजन को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था। कंपनी ने अब इसे आरडीई नियमों के साथ पेश किया है। नई इनोवा में आने वाला 2.4 L डीजल इंजन 150 बीएचपी की शक्ति और 343Nm का पीक टॉर्क प्रदान करता है। ये इंजन 5-स्पीड मैनुअल (MT) और 6-स्पीड आटोमेटिक (AMT) गियरबॉक्स विकल्प के साथ उपलब्ध है।

मिलेंगे ये फीचर्स

टोयोटा अपनी डीजल इंजन वाली नई Innova Crysta में स्पीडोमीटर, ड्राइवर विंडो पर ऑटो डाउन के साथ पावर विंडो, मैनुअल एसी यूनिट, ब्लैक फैब्रिक सीट कवर, डोर इनसाइड हैंडल इंटीरियर कलर दे रही है। वहीं इसमें हेड-अप डिस्प्ले, वायरलेस चार्जर, एयर आयोनाइजर और 16 रंगों के साथ डोर एज लाइटिंग और 8.0-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। कंपनी इसमें मल्टी टेरेन मॉनिटर (360-डिग्री कैमरा), 3 SRS एयरबैग, EBD के साथ ABS, हिल स्टार्ट असिस्ट, ब्रेक असिस्ट, सीट बेल्ट वार्निंग, डोर अजर वार्निंग और इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम जैसे सेफ्टी फीचर्स ऑफर करती है।

20 लाख से कम कीमत पर आती हैं ये सबसे सेफ कारें 5-स्टार रेटिंग के साथ मिलते हैं ये सेफ्टी फीचर्स

हम आपको 20 लाख रुपये से कम कीमत पर आने वाली 5 सबसे सेफ कारों के बारे में बताने जा रहे हैं। हमारी इस सूची में Mahindra XUV300 से लेकर Volkswagen Taigun तक शामिल है।

नई दिल्ली। आज के समय में सेफ्टी सबसे महत्वपूर्ण विषय है। हम लोग कार खरीदते हुए भी इस बात को ध्यान में रखते हैं। लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं और रोड पर हो रही अनियमितताओं के चलते लोग अपने बजट में सबसे सेफ कार खोजते हैं। आज के इस लेख में हम आपको 20 लाख रुपये से कम कीमत पर आने वाली 5 सबसे सेफ कारों के बारे में बताने जा रहे हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि इन कारों में कौन से सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं और इनकी सेफ्टी रेटिंग क्या है। हमारी इस सूची में Mahindra XUV300 से लेकर Volkswagen Taigun तक शामिल है।

Tata Punch

Tata Punch को Tata Altroz के समान प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। एक समय में भारत में सबसे सुरक्षित कार का खिताब Tata Altroz के पास ही था। Tata Punch में एबीएस, ईबीडी, ड्यूल एयरबैग्स और ब्रेक स्वे कंट्रोल सहित कई सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। साथ ही इसके एएमटी वेरिएंट में ट्रैक्शन प्रो मोड मिलता है जो ड्राइवरों को फिसलन और अनियमित सतहों पर चलने में मदद करता है। Tata Punch को Global NCAP में 5-स्टार रेटिंग मिली है। वहीं इसकी चाइल्ड ऑक्यूपेंट रेटिंग भी 4-स्टार है। आप Tata Punch को 6 लाख रुपये की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत पर खरीद सकते हैं।

Mahindra XUV300

Mahindra XUV300 को देश की सबसे सेफ Compact SUV माना जाता है। Mahindra की ये कॉम्पैक्ट एसयूवी 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है। वहीं इस कार को चाइल्ड ऑक्यूपेंट कैटेगरी में भी 4 स्टार मिले हैं। Mahindra XUV300 कॉर्नर ब्रेक, 7 एयरबैग, एबीएस और ईबीडी जैसे सेफ्टी फीचर्स के साथ आती है। कंपनी की ये SUV काफी सुरक्षित है और मजबूत बॉडी के साथ आती है। Mahindra अपनी इस कार को 8.41 लाख रुपये की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत पर बेचती है।

Volkswagen Taigun

VW Taigun को हाल के ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार मिले हैं। देश में बिकने वाली Volkswagen की इस कार ने वयस्क और बच्चों दोनों की सुरक्षा के लिए 5-स्टार की रेटिंग हासिल की है। वहीं सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो Taigun में 6 एयरबैग (ड्राइवर, फ्रंट पैसेंजर, दो पर्दे, ड्राइवर साइड और फ्रंट पैसेंजर साइड), मल्टी-टक्कर ब्रेक, ऑटो हिल-होल्ड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, पार्क डिस्टेंस कंट्रोल, रियर व्यू कैमरा और 3-पॉइंट सीट बेल्ट दिए गए हैं। साथ ही इसमें साइड इम्पैक्ट प्रोटेक्शन बीम, क्रम्पल जोन, और अन्य निष्क्रिय सुरक्षा सुविधाएं भी मिलती हैं। आप इसको 11.62 लाख रुपए की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत पर खरीद सकते हैं।

Skoda Kushaq

Volkswagen Taigun की तरह ही Skoda Kushaq ने भी वयस्क और बच्चे दोनों श्रेणियों के लिए नवीनतम क्रैश टेस्ट में 5 स्टार ग्लोबल NCAP रेटिंग हासिल की है। इस कार में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल और हाई वेरिएंट पर छह एयरबैग जैसे कई सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। साथ ही इसमें एंटी लॉक ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, मल्टी-कोलिजन ब्रेक, XDS के साथ इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। कंपनी अपनी इस कार को 11.59 लाख रुपए की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत पर बेचती है।

Mahindra Scorpio N

ग्लोबल एनसीएपी सुरक्षा परीक्षणों के हालिया दौर में Mahindra Scorpio N को 5-स्टार रेटिंग प्राप्त हुई है। हालांकि चाइल्ड ऑक्यूपेंट टेस्ट में इसे केवल 3-स्टार रेटिंग ही मिली है। इस 7-सीटर एसयूवी के बेस मॉडल में मजबूत बॉडीशेल के अलावा डुअल एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, रियर पार्किंग सेंसर और आईएसओफिक्स एंकर शामिल हैं। वहीं इसमें ESC, हिल-होल्ड कंट्रोल, हिल-डिसेंट कंट्रोल, साइड और कर्टन एयरबैग और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। आप इस एसयूवी कार को 12.74 लाख रुपए की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत कर खरीद सकते हैं।

मजबूत डिजिटल ढांचे की अहमियत

डा. जयंतीलाल भंडारी

भारत में वर्ष 2014 से लागू की गई डीबीटी योजना एक वरदान की तरह दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से डिजिटल समानता से समाज के सभी वर्गों की पहुंच डिजिटल प्रौद्योगिकी की ओर बढ़ गई है। भारत में डीबीटी से कल्याणकारी योजनाओं के जरिए महिलाओं, बुजुर्गों और किसानों और कमजोर वर्ग के लोगों को अकल्पनीय फायदा हो रहा है'

इन दिनों देश और दुनिया के विभिन्न प्रमुख आर्थिक और वित्तीय संगठनों की रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि भारत में डिजिटलीकरण से आर्थिक कल्याण और अर्थव्यवस्था के विकास का नया दौर दिखाई दे रहा है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ)के द्वारा प्रकाशित वर्किंग पेपर 'स्टैकिंग अप द बेनेफिट्स लेसन्स फ्रॉम इंडियाज डिजिटल जर्नी' में कहा गया है कि डिजिटलीकरण ने भारत की अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने में मदद की है और आधार ने लीकेज को कम करते हुए लाभार्थियों को भुगतान के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर डीबीटी)में मदद की है। साथ ही मार्च 2021 तक डिजिटल बुनियादी ढांचे और अन्य डिजिटल सुधारों के कारण व्यय में जीडीपी का लगभग 1.1 फीसदी बचाया गया है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) की सराहना दुनिया भर में की जा रही है। इस समय देश में करीब 47.8 करोड़ से अधिक जनधन खातों, (जे) करीब 134 करोड़ से अधिक आधार कार्ड (ए) और 118 करोड़ से अधिक मोबाइल उपभोक्ताओं (एम) के तीन आयामी जैम से आम आदमी डिजिटल दुनिया से जुड़ गया है। भारत में वर्ष 2014 से लागू की गई डीबीटी योजना एक वरदान की तरह दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से डिजिटल समानता से समाज के सभी वर्गों की पहुंच डिजिटल प्रौद्योगिकी की ओर बढ़ गई है। भारत में डीबीटी से कल्याणकारी योजनाओं के जरिए महिलाओं, बुजुर्गों और किसानों और कमजोर वर्ग के लोगों को अकल्पनीय फायदा हो रहा है। उल्लेखनीय है कि 3 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीआई के डायमंड जुबली समारोह में कहा कि सरकार ने वर्ष 2014 से लेकर अब तक डीबीटी के जरिए करीब 27 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि सीधे लाभान्वितों के बैंक खातों तक पहुंचाई गई है। केंद्र सरकार के द्वारा गरीबों, किसानों और कमजोर वर्ग के करोड़ों लोगों के बैंक खातों में डीबीटी से सीधे सब्सिडी जमा कराए जाने से करीब सवा दो लाख करोड़ रुपए बिचौलियों के हाथों में जाने से बचाए गए हैं।

निसंदेह भारत ने पिछले एक दशक में मजबूत डिजिटल ढांचे से डिजिटलीकरण में एक लंबा सफर तय कर लिया है। सरकारी योजनाओं के तहत बिचौलियों के भ्रष्टाचार को रोकने, काम के भौतिक रूपों व सरकारी कार्यालयों में लंबी कतारों से राहत और घरों में आराम से मोबाइल स्क्रीन पर कुछ क्लिक करके विभिन्न सेवाओं, सुविधाओं और मनोरंजन की सहज उपलब्ध

सुविधाएं हैं। ज्ञातव्य है कि जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की 450 से अधिक सरकारी योजनाओं का फायदा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाने में बड़ी कामयाबी मिली है, वहीं लोगों की सुविधाएं बढ़ी हैं। देश में सौ से अधिक सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। पहले बैंक, गैस, स्कूल, टोल, राशन हर जगह कतारें होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सरकारी दफ्तर आपकी मुठ्ठियों में रखें मोबाइल तक पहुंच गए हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है कि छोटे उद्योग, कारोबार के लिए सरल ऋण और रोजगार सृजन हेतु अप्रैल 2015 को डिजिटल रूप से लागू प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मार्च 2023 तक 40.82 करोड़ लोन खातों में 23.2 लाख करोड़ रुपए पहुंचाए गए हैं। इसी तरह अटल पेंशन योजना, भारत बिल भुगतान प्रणाली, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, स्टैंड अप इंडिया और तत्काल भुगतान सेवा, डिजिटल आयुष्मान भारत मिशन से भी समाज के करोड़ों लोग लाभांवित हो रहे हैं। डिजिटल पैमेंट के मामले में भारत दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल है और भारत में अमरीका, यूके और जर्मनी जैसे बड़े देशों को पीछे कर दिया है। ये सब सेवाएं भारत में डिजिटल गवर्नेंस के एक नए युग की प्रतीक हैं।

इतना ही नहीं किसानों के समावेशी विकास में भी डीबीटी की अहम भूमिका है। एक जनवरी 2023 से डिजिटल राशन प्रणाली से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाय) के तहत 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को हर महीने खाद्यान्न निशुल्क प्रदान किया जा रहा है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुताबिक 27 फरवरी 2023 तक किसान सम्मान निधि योजना के तहत 13 किस्तों में 11 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में डीबीटी से सीधे करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक हस्तांतरित किए जा चुके हैं। यह अभियान दुनिया के लिए मिसाल बन गया है और इससे छोटे किसानों का वित्तीय सशक्तिकरण हो रहा है। वस्तुतः देश में बढ़ते हुए डिजिटलीकरण ने रोजगार के नए डिजिटल अवसर भी पैदा किए हैं। कोरोना की चुनौतियों के बीच भारत के आईटी सेक्टर के द्वारा समय पर दी गई गुणवत्तापूर्ण सेवाओं से वैश्विक उद्योग, कारोबार इकाइयों का भारत की आईटी कंपनियों पर भरोसा बढ़ा है। डिजिटल इकोनॉमी के तहत कॉमर्स, बैंकिंग, मार्केटिंग, ट्रांजेक्शन, डेटा एनालिसिस, सायबर सिक्योरिटी, आईटी, टूरिज्म, रिटेल ट्रेड, हॉस्पिटेलिटी आदि क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार के चमकीले मौके बढ़ते जा रहे हैं। ये मौके भारत की नई पीढ़ी के लिए देश ही नहीं दुनियाभर में विस्तारित हो रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध मैकिंजी ग्लोबल इंस्टीच्यूट के द्वारा वैश्विक रोजगार रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में डिजिटल ढांचे की मजबूती के कारण अर्थव्यवस्था में वर्ष 2025 तक डिजिटलीकरण से करीब 2 करोड़ से अधिक नई नौकरियां निर्मित होते हुए दिखाई देंगी। यह भी महत्त्वपूर्ण है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने देश में डिजिटल रुपए के नए दौर की जिस तरह शुरुआत की है, यह आने वाले दिनों में गेमचेंजर साबित हो सकती है।

यह भी कोई छोटी बात नहीं है कि देश में विभिन्न डिजिटल प्लेटफार्मों पर एक अरब से अधिक लोगों के डेटा को सुरक्षित बनाए रखने के लिए साइबर स्वच्छता केंद्र (सीएके) अहम भूमिका निभा रहा है। लेकिन मजबूत डिजिटल ढांचे की विभिन्न उपयोगिताओं के बावजूद इस समय देश में डिजिटलीकरण के तहत स्टार्टअप, डिजिटल शिक्षा, डिजिटल बैंकिंग, भुगतान समाधान, स्वास्थ्य तकनीक, एग्रीटेक आदि की डगर पर जो बाधाएं और चुनौतियां दिखाई दे रही हैं, उनके समाधान हेतु तत्परतापूर्वक कदम उठाए जाने जरूरी हैं। हम उम्मीद करें कि सरकार आईएमएफ के वर्किंग पेपर के मद्देनजर देश के मजबूत डिजिटल ढांचे को ध्यान में रखते हुए जहां और अधिक सेवाओं को डिजिटलीकरण की छतरी में लाएगी, वहीं दुनिया के जरूरतमंद देशों को भी डिजिटल ढांचे से लाभांवित करेगी। हम उम्मीद करें कि सरकार नई शिक्षा प्रणाली के तहत भारत में डिजिटलीकरण को अधिक गतिशील बनाने के लिए नई पीढ़ी को नए दौर की डिजिटल स्किल्स और उन्नत प्रौद्योगिकियों से शिक्षित प्रशिक्षित करने की डगर पर तेजी से आगे बढ़ेगी। हम उम्मीद करें कि सरकार देश में अधिक तकनीकी एवं वैज्ञानिक सोच, डेटा तक सरल पहुंच, स्मार्टफोन की कम लागत, निर्बाध कनेक्टिविटी, बिजली की सरल आपूर्ति, जैसी जरूरतों पर और अधिक ध्यान देंगी। हम उम्मीद करें कि इस समय जब इस वर्ष 2023 में भारत की मुठ्ठियों में जी-20 की अध्यक्षता है तब भारत के द्वारा जी-20 सदस्यों के बीच आम सहमति से एक लाभपूर्ण और सुरक्षित साइबर स्पेस के लिए प्रभावी पहल की जाएगी।

संपादक की कलम से

शर्मसार वे कर रहे हैं'

यकीनन पीटी उषा 1970-80 के दशक की महान धाविका थीं। उनकी तुलना भारत के ही महान 'उडऩ सिख' मिल्खा सिंह से की जाती थी। दोनों में साम्य यह रहा कि वे पलक झपकने की देरी से ओलंपिक पदक चूक गए थे, लेकिन वे फिर भी महान खिलाड़ी रहे। एशिया, राष्ट्रमंडल स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में उन्होंने मिसाल कायम की और भारत के लिए सम्माननीय पदक भी हासिल किए। मिल्खा सिंह आज दिवंगत हैं, जबकि पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद हैं। सिर्फ एक ही बयान अथवा सोच के आधार पर उन्हें सोशल मीडिया और अखबारों में ट्रोल किया जा रहा है। आलोचनाएं की जा रही हैं। लानत-मलानत तक की नौबत आ गई है। पीटी उषा का यह अपमान भी स्वीकार्य नहीं है। एक किस्म का अन्याय है। अलबत्ता इस बार भी वह चूक गईं। इस बार लक्ष्य दौड़ का नहीं था, बल्कि खिलाडियों के प्रति संवेदनशीलता और विनम्र व्यापकता का था। उषा वरिष्ठ, पद में बड़ी और अनुभव में विराट हैं, लिहाजा वह धरने पर बैठे पदकवीर पहलवानों से मिलने जा सकती थीं। उनके साथ फुटपाथ पर बैठकर विमर्श कर सकती थीं और सिर पर दिलासा, समर्थन का हाथ रख सकती थीं। जो राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक सप्ताह से पड़े हुए हैं। वहीं सोते-जागते, खाते-पीते और अपना अभ्यास भी कर रहे हैं। कमोबेश उषा को उन्हें 'अनुशासनहीन' करार नहीं देना चाहिए था। जो महिला पहलवान अपनी इज्जत के लिए इंसाफ मांग रही हैं, वे देश को शर्मसार नहीं कर रहीं। उन्होंने तो अंतरराष्ट्रीय फलक पर 'तिरंगे' को गौरवान्वित किया है।

खेल और भारत की छवि पर कीचड़ वे मथ रहे हैं, जिन पर नाबालिग पहलवान के यौन-उत्पीडऩ का बेहद गंभीर आरोप है। देश की व्यवस्था को शर्मसार वे कर रहे हैं, जिन्होंने 'पॉक्सो कानून' के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के बावजूद आरोपितों को गिरफ्तार नहीं किया है। कानून में स्पष्ट प्रावधान है कि ऐसे 'दरिन्दे' की 100 फीसदी गिरफ्तारी तय की जानी चाहिए। चूंकि मुख्य आरोपित बाहुबली है, अपराधी है और भाजपा का विजयी सांसद है, लिहाजा कानून की भी खिल्ली उड़ाई जा रही है। देश और उसकी लोकतांत्रिक, संवैधानिक आत्मा को शर्मसार वे कर रहे हैं, जो रात में धरना-स्थल की बत्ती गुल कर रहे हैं, जिन्होंने पेयजल और दूसरे पानी के टैंकर वहां से हटा लिए हैं, जिन्होंने सार्वजनिक शौचालय की सुविधा भी छीनने की साज़िश की है। पुलिस भी मानसिक अत्याचार करने पर तुली है। शर्मनाक है कि जिन पदकवीर खिलाडियों के लिए हमने पलक-पांवड़े बिछाए थे, उन्हीं के लिए प्रधानमंत्री समेत सरकार और पीटी उषा सरीखे पदेन चेहरे 'संवेदनहीन' हो गए हैं। आखिर कुछ महान खिलाडियों की चेतना ने बाध्य किया है कि धरना दे रहे पदकवीर पहलवानों का समर्थन करें। इनमें सबसे बड़ा नाम टोक्यो ओलंपिक के एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता, भारतीय भाला-फेंक खिलाड़ी, नीरज चोपड़ा का है। कपिलदेव, भुटिया, अभिनव बिन्द्रा, हरभजन सिंह, वीरेन्द्र सहवाग, मनु भाकर, सानिया मिजऱा, निक़हत जऱीन आदि विश्व विख्यात खिलाडियों ने पहलवानों के विरोध-प्रदर्शन को समर्थन दिया है। राजनेताओं की अपनी भूमिका है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आह्वान किया है कि दिल्लीवाले छुट्टी लेकर जंतर-मंतर पहुंचें और अपने राष्ट्रीय नायकों का समर्थन करें। यह मुद्दा फिलहाल राजनीतिक नहीं बना है, लेकिन विभिन्न राजनीतिक धाराओं के नेतागण पहलवानों के सरोकार का समर्थन करने पहुंच रहे हैं।

मेरी राय

चुनाव की आंखों में शिमला

शिमला नगर निगम चुनाव केवल राजनीतिक करवटों और कसौटियों की जंग नहीं, बल्कि शहरी एहसास व नागरिक जागरूकता का पैमाना भी है। नागरिक समाज की श्रेष्ठता में सवाल उस चेतना से जुड़ जाते हैं, जिन्हें उठाकर चलते हुए राजधानी शिमला कहीं बूढ़ी, कहीं थकी, कहीं हारी, तो कहीं पश्चाताप करती हुई ऐसी लाठी ढूंढ रही है, जिसके दम पर कुछ नए कदम उठाए जा सकते हैं। ये कदम घटते-बढ़ते वार्डों की शिनाख्त में भी नहीं, बल्कि राजधानी होने की पैमाइश के लिए जरूरी हैं। शिमला में हिमाचल को खोजें, तो ऊंची इमारतों के साये में अस्त-व्यस्त जिंदगी की गुमनामियों के ढेर पर खुद की खुरचने की मजबूरियां दर्ज होती हैं। मजबूरियां एक राजधानी की, शहर की, उम्मीदों की, नागरिक सुविधाओं की और पूरे प्रदेश की आंखों में विकास के उस काजल की, जो शिमला की आंखों में आंसुओं सहित बह रहा है। ऐसे में हमारी प्रतीक्षा अगर बड़े टकराव और विभिन्न पार्टियों के रंग-रोगन में सजे ख्याली पुलाव तक ही सीमित है, तो उम्मीदवारों के चेहरे नहीं, पार्टियों के दमखम में एक छोटी सत्ता का संघर्ष देखिए। शिमला के अपने दायरे, अपने मजमून हैं, जो चुनाव को बड़ी अदालत बना देते हैं। यहां स्मार्ट सिटी की सीढियां हैं, लेकिन इतिहास की पाजेब पहनकर शहर कहीं ढलान से उतर कर आधुनिकता के गोबर में अपने कदम गंदे कर चुका है। इसमें दो राय नहीं कि यह नई संरचना का शहर नहीं हो सकता, लेकिन नए संकल्प तो जोड़ सकता है, वरना विभ्रम में शिमला अपनी ही कंदराओं में भटक रहा है। जाहिर है चुनाव के मुद्दे वार्डों की परिक्रमा करेंगे और फिर सभी मिलजुल कर सियासत के परिंदे पैदा करेंगे। अप्रत्यक्ष चुनाव से मेयर पद पर प्रत्यक्ष प्रमाणिकता कैसे आएगी, यह विशुद्ध सियासी प्रश्न है, इसलिए नगर निगम की व्यवस्था अलग और कर्मठता अलग से दिखाई देगी। बहरहाल सियासी सूचियों में खुलते लिफाफे और गर्द झाड़ते नेताओं के चंगुल में शहर को एक जीत की तलाश है। राजनीतिक जीत में शहर के बीच फासलों की मुनादी करते प्रयत्न अगर सपनों के अंगूरों को खट्टा न करें, तो जनता की काबिलीयत में यह चुनाव जीता जा सकता है। चुनाव वहां जीता जाएगा, जहां शिमला सिसकता है। क्या शिमला शहर में किसी सत्ता की खोज अपरिहार्य है या उस सुकून की प्राप्ति होगी जो कभी मालरोड की सफाई पर इतराता था। भीड़ के जंगल में कितना अकेला है शिमला, फिर भी यह चुनाव सियासत की भीड़ से दरख्वास्त कर रहा कि इस बार कुछ संवेदनशील, विजन से भरपूर और सियासत से ऊपर उठे हुए कुछ पार्षद दे देना। आश्चर्य यह कि शिमला चुनाव में सियासत के बीज पूरी शिद्दत से बोए जा रहे हैं और नागरिक इच्छा है कि परिणामों के साथ शिमला के बागीचे में फूल उगेंगे। यह संभव है, लेकिन क्या इससे पूर्व न्यू शिमला में सुकून उगा पाए या स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत राजधानी ने खुद को स्मार्ट कर लिया। शिमला के अपने मायने, अपना शिष्टाचार, अपना व्यवहार व जीवन शैली रही है, लेकिन अब बरसात की धुंध भी इसकी विकृतियों को नहीं छुपा पाती। पर्यटक सीजन के उत्साह में जेब भरता एक शिमला इतना परवान चढ़ जाता है कि सारी हरियाली पहले भूरी और फिर कंक्रीट के नीचे दब जाती है। दब जाती हैं सडक़ें जब शहर का हाल पूछने पर्यटक सीजन आता है। तब नागरिक आंख उठाकर नहीं देख पाते और जो सुनते हैं, उसमें शिमला की हवाओं का स्पर्शन दारद है। इन्हीं कानों ने बार-बार सुना कि अबकि बार ट्रैफिक तंग नहीं करेगा, कोई स्काई बस आकर भीड़ को गंतव्य तक ले जाएगी। अब फिर सुनाया जा रहा है कि शिमला में रैपिड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का सारा बोझ पर्वतमाला के तहत रज्जुमार्ग उठा लेगा। शिमला नगर निगम चुनाव अपने साथ, अपने ही आंकड़ों के मजाक में शरीक रहता है या यह सोच पाता है कि उसे अपने भीतर राज्य की कितनी राजधानी, कितना पर्यटन, कितनी व्यावसायिक हलचल, कितने राजनीतिक मंतव्य या नागरिक रिश्ते संवारने हैं।

मौजूदा दौर में श्रमिक दिवस की प्रासंगिकता

उद्योग, व्यापार, भवन निर्माण, पुल, सडक़ों का निर्माण, कृषि इत्यादि समस्त क्रियाकलापों में श्रमिकों के श्रम का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है और वर्तमान मशीनी युग में भी उनकी महत्ता कम नहीं है। सही मायनों में विश्व की उन्नति का दारोमदार इसी वर्ग के मजबूत कंधों पर होता है। किसी भी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति तथा राष्ट्रीय हितों की पूर्ति का प्रमुख भार श्रमिक वर्ग के कंधों पर होता है। समाज के इसी वर्ग के लिए प्रतिवर्ष 1 मई को 'अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस' अथवा 'मजदूर दिवस' मनाया जाता है, जिसे 'मई दिवस' भी कहा जाता है। भारत में श्रमिक दिवस मनाए जाने की शुरुआत किसान मजदूर पार्टी के कामरेड नेता सिंगारावेलू चेट्यार के सुझाव पर 1 मई 1923 को हुई थी। उनका कथन था क्योंकि दुनियाभर के मजदूर इस दिन को मनाते हैं, इसलिए भारत में भी इसे मनाया जाना चाहिए। इस प्रकार भारत में 1 मई 1923 से मई दिवस को राष्ट्रीय अवकाश के रूप मान्यता दी गई। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाए जाने की शुरुआत अमरीका में 8 घंटे से ज्यादा काम न कराने के लिए की गई कुछ मजदूर यूनियनों की हड़ताल के बाद 1 मई 1886 से हुई थी। दरअसल वह ऐसा समय था, जब कार्यस्थल पर मजदूरों को चोट लगना या काम करते समय उनकी मृत्यु हो जाना आम बात थी। ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने, कार्य करने के घंटे कम करने तथा सप्ताह में एक दिन के अवकाश के लिए मजदूर संगठनों द्वारा पुरजोर आवाज उठाई गई। 1 मई 1886 का ही वह दिन था, जब वह हड़ताल हुई थी और शिकागो शहर के हेय मार्केट चौराहे पर उनकी रोज सभाएं होती थी। 4 मई 1886 को जब शिकागो के हेय मार्केट में उस हड़ताल के दौरान पुलिस भीड़ को तितर-बितर करने का प्रयास कर रही थी, उसी दौरान किसी अज्ञात शख्स ने एकाएक भीड़ पर बम फैंक दिया।

उसके बाद पुलिसिया गोलीबारी के कारण कई श्रमिक मारे गए। हालांकि उस समय अमरीकी प्रशासन पर उन घटनाओं का कोई असर नहीं पड़ा लेकिन बाद में श्रमिकों के लिए 8 घंटे कार्य करने का समय निश्चित कर दिया गया। मजदूरों पर गोलीबारी और मौत के दर्दनाक घटनाक्रम को स्मरण करते हुए ही 1 मई 1886 से अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाने लगा। 1889 में पेरिस में अंतरराष्ट्रीय महासभा की द्वितीय बैठक में फ्रांसीसी क्रांति को याद करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया कि इसे 'अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस' के रूप में मनाया जाए। उसी समय से विश्वभर के 80 देशों में 'मई दिवस' को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मान्यता प्रदान की गई। भारत में 'मई दिवस' मनाए जाने की शुरुआत किसान मजदूर पार्टी के कामरेड नेता सिंगारावेलू चेट्यार के सुझाव पर 1 मई 1923 को हुई थी। उनका कथन था कि दुनियाभर के मजदूर इस दिन को मनाते हैं, इसलिए भारत में भी इसे मनाया जाना चाहिए। इस प्रकार भारत में 1 मई 1923 से मई दिवस को राष्ट्रीय अवकाश के रूप मान्यता दी गई। श्रमिक वर्ग ही है, जो अपनी मेहनत के बलबूते पर राष्ट्र के प्रगति चक्र को तेजी से घुमाता है लेकिन कर्म को ही पूजा समझने वाला यह वर्ग श्रम कल्याण सुविधाओं के लिए आज भी तरस रहा है। मई दिवस के अवसर पर देशभर में भले ही मजदूरों के हितों की बड़ी-बड़ी योजनाएं बनती हैं, ढ़ेरों लुभावने वायदे किए जाते हैं, जिन्हें सुनकर एकबारगी तो लगता है कि उनके लिए अब कोई समस्या नहीं बचेगी, किंतु अगले ही दिन मजदूरों को पुनः उसी माहौल से रू-ब-रू होना पड़ता है, फिर वही शोषण, अपमान और जिल्लत भरा जीवन जीने के लिए अभिशप्त होना पड़ता है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर किसके लिए मनाया जाता है 'श्रमिक दिवस'? बहुत से मजदूरों की तो इस दिन भी काम करने के पीछे यही मजबूरी होती है कि यदि वे एक दिन भी काम नहीं करेंगे, तो उनके घरों में चूल्हा कैसे जलेगा? विडंबना है कि देश की स्वाधीनता के साढ़े सात दशक से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी अनेक श्रम कानूनों को अस्तित्व में लाने के बावजूद हम ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कर पाए हैं, जो मजदूरों को उनके श्रम का उचित मूल्य दिला सके। भले ही इस संबंध में कई कानून बने हैं, किंतु श्रमिक वर्ग की समस्याएं इसके बावजूद कम नहीं हैं।

हालांकि सच यह भी है कि अधिकांश श्रमिक या तो अपने अधिकारों के प्रति अनभिज्ञ होते हैं या वे अपने अधिकारों के लिए इस कारण आवाज नहीं उठा पाते कि कहीं इससे नाराज होकर उनका मालिक उन्हें काम से न निकाल दे और उनके परिवार के समक्ष भूखे मरने की नौबत आ जाए। जहां तक मजदूरों द्वारा अपने अधिकारों की मांग का सवाल है तो मजदूरों के संगठित क्षेत्र द्वारा ऐसी मांगों पर उन्हें अकसर कारखानों के मालिकों की मनमानी और तालाबंदी का शिकार होना पड़ता है और प्रायः जिम्मेदार अधिकारी भी कारखानों के

> "किसी भी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति तथा राष्ट्रीय हितों की पूर्ति का प्रमुख भार श्रमिक वर्ग के कंधों पर होता है। समाज के इसी वर्ग के लिए प्रतिवर्ष 1 मई को 'अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस' अथवा 'मजदूर दिवस' मनाया जाता है, जिसे 'मई दिवस' भी कहा जाता है'

मालिकों के मनमाने रवैये पर लगाम लगाने की चेष्टा नहीं करते। जहां तक मजदूर संगठनों के नेताओं द्वारा मजदूरों के हित में आवाज उठाने की बात है तो आज के दौर में अधिकांश ट्रेड यूनियनों के नेता भी भ्रष्ट राजनीतिक तंत्र का हिस्सा बने हैं, जो विभिन्न मंचों पर श्रमिकों के हितों के नाम पर शोर तो बहुत मचाते नजर आते हैं लेकिन अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति हेतु कारखानों के मालिकों से सांठगांठ कर अपने ही श्रमिक साथियों के हितों पर कुल्हाड़ी चलाने में संकोच नहीं करते। श्रमिक दिवस और श्रम के महत्व को रेखांकित करते हुए एडम स्मिथ ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा था कि दुनिया की सारी संपदा को सोने अथवा चांदी से नहीं, बल्कि मजदूरी के द्वारा खरीदा जा सकता है।

अब्राहम लिंकन ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति कहे कि वह अमरीका पर भरोसा करता है, फिर भी मजदूर से डरता है तो वह एक बेवकूफ है और अगर कोई कहे कि वह अमरीका से प्यार करता है, फिर भी मजदूर से नफरत करता है तो वह झूठा है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के शब्दों में कहें तो इंसानियत को ऊपर उठाने वाले सभी श्रमिकों की अपनी प्रतिष्ठा और महत्व है। अतः श्रम साध्य उत्कृष्टता के साथ किया जाना चाहिए। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का कहना था कि किसी व्यवसाय को ऐसे देश में जारी रहने का अधिकार नहीं है, जो अपने श्रमिकों से जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक मजदूरी से भी कम मजदूरी पर काम करवाता है। जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक मजदूरी से उनका आशय सम्मानपूर्वक जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक मजदूरी से था।

चिंतन विचार

युवा कुंठा के ताले खोलें

प्रदेश के वित्तीय संसाधनों को पूरी तरह सरकारी कर्मचारियों के खेत में जोतने के बजाय, युवाओं के भविष्य और उनकी क्षमता के इजहार से नत्थी करना होगा। एक लाख सरकारी नौकरियों संबंधी मंत्रिमंडलीय उप समिति के गठन का मनोवैज्ञानिक प्रभाव हर युवा के सपनों को शिखर पर पहुंचा रहा है,लेकिन इसके साथ अगर इसी तरह की समितियां स्वरोजगार के अवसरों, कृषि-बागबानी व ग्रामीण आर्थिकी के जरिए युवाओं को साहसिक कदम उठाने की तरफ ले जाएं, तो युवा मुस्कराहट के बहाने बढ़ेंगे।

हिमाचल की प्राथमिकताओं में सियासी पंजे हमेशा अल्पाविधि के जीत बिंदुओं पर दबाव बनाते रहे हैं, नतीजतन सामाजिक, आर्थिक असंतुलन के कई रिसाव पैदा होते गए। विडंबना यह भी कि समाजशास्त्री और न ही अर्थशास्त्री एक सीमा के बाहर यह नहीं सोच पाए कि प्रदेश के भविष्य में युवा शक्ति का आरोहण किस दिशा में मोड़ा जाए। प्रदेश की प्राथमिकताओं का चुनावी ध्रुवीकरण भी कुछ इस तरह हुआ कि हर बार वही पूजे गए जो सत्ता के नजदीक देखे गए। सत्ता के नजदीक बेरोजगार युवा नहीं, बल्कि सरकारी नौकरी में रहे लोग ही आजमाए जा रहे हैं। बजट के आबंटन में प्रदेश की सूरत केवल सरकारी इमारतों के ऊपर पताका फहराती हुई मिलेगी या चौबीस घंटे सरकारों की मंत्रणा में वही नौकरीपेशा लोग अग्रणी हैं, जो हमेशा रूठे रहने की मुद्रा में प्रदेश की नीतियों को बरगला सकते हैं। ऐसे में किसी भी सरकार के सरकारी कार्यालयों में कर्मचारी आक्रोश को तो कद और औकात से कहीं अधिक शांत करने की कोशिश की गई मगर, हर घर में बैठे बेरोजगार युवा के आक्रोश को निरंतरता से नहीं समझा। यही युवा किसी विभ्रम में फंसाया जाता है और सरकारी नियुक्तियों से बहकाया जाता है, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद न तो इस तरह सभी को खुश किया जा सकता है और न ही इनकी कुंठाओं के ताले खोले जाने का कभी कोई विकल्प तैयार होता है। युवाओं में आक्रोश की वजह सरकार की नीतियां नहीं, बल्कि समाज की दृष्टि भी है। हमारी शिक्षा की प्रणाली और मात्रात्मक शिक्षा की तरफदारी भी युवाओं को ऐसे मोड़ पर ले आई है, जहां अपनी ही काबिलीयत के बलबूते प्रतिस्पर्धा के कठिन रास्ते चुनने से युवा कतराने लगा है। जरा सोचिए युवा कब और कहां और किस तरह के व्यवहार में संलिप्त मिल रहा है। जिंदगी के पथ को आसान करने की सियासी भाषा हमेशा से फरेबी रही और जिसने गांव में स्कूल तो दे दिया, लेकिन खेत से कितने हाथ छीन लिए, कोई नहीं जानता। डिग्रियों के बाजारों में युवाओं का मुजरा करवाने वालों ने यह नहीं सोचा कि कल यही बच्चे जब सपनों के आकाश से नीचे गिर कर खजूर पर लटकेंगे, तो उनकी चीख कौन सुनेगा। ऐसी कई राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के तहत नौकरियों का उत्कृष्ट माहौल खड़ा है, लेकिन प्रदेश में उन्हें प्रेरित कौन करेगा। सरकार को हर राष्ट्रीय परीक्षा के केंद्र हिमाचल में भी खुलवाने होंगे। मौटे तौर पर सोलन, धर्मशाला, मंडी और हमीरपुर में राज्य स्तरीय परीक्षा केंद्रों की अधोसंरचना विकसित करनी चाहिए। इसके लिए बागबानी विश्वविद्यालय, स्कूल शिक्षा बोर्ड, मंडी यूनिवर्सिटी तथा तकनीकी विश्वविद्यालय के परिसरों में ऐसी अधोसंरचना विकसित की जा सकती है। आज प्रदेश में युवाओं का एक वर्ग नशे की गिरफ्त में क्यों जा रहा है, यह सोचना होगा। इसके लिए शिक्षा, साहित्य, संस्कृति, समाज और ग्रामीण रहन सहन की पृष्ठभूमि को प्रभावशाली बनाने की जरूरत है। युवाओं के व्यवहार में आ रही विकृतियों में अलग तरह के निराशावाद को चिन्हित करते हुए, कम से कम सरकारी स्तर पर नई प्राथमिकताओं का इजहार करते हुए, प्रदेश की प्राथमिकताओं में उन्हें हर स्तर पर चिन्हित करना होगा।

प्रदेश के वित्तीय संसाधनों को पूरी तरह सरकारी कर्मचारियों के खेत में जोतने के बजाय, युवाओं के भविष्य और उनकी क्षमता के इजहार से नत्थी करना होगा। एक लाख सरकारी नौकरियों संबंधी मंत्रिमंडलीय उप समिति के गठन का मनोवैज्ञानिक प्रभाव हर युवा के सपनों को शिखर पर पहुंचा रहा है,लेकिन इसके साथ अगर इसी तरह की समितियां स्वरोजगार के अवसरों, कृषि-बागबानी व ग्रामीण आर्थिकी के जरिए युवाओं को साहसिक कदम उठाने की तरफ ले जाएं, तो युवा मुस्कराहट के बहाने बढ़ेंगे।

युवाओं को सहजता से जीवन की कठिन कसौटियों में पारंगत करने की दिशा में स्कूल, कालेज और विश्वविद्यालयों को अपने पाठ्यक्रम, अध्ययन-अध्यापन की परिपाटी और व्यावहारिक ज्ञान की रूपरेखा बदलनी पड़ेगी, ताकि उम्मीदें और सपने केवल सरकारी नौकरी तक सीमित होकर ही न रह जाएं। हमारा राजनीतिक समर्थन सत्ता की प्राप्ति के लिए हमेशा कर्मचारी खुशामद का परवाना बना रहा, जबकि इससे कहीं अधिक समर्थन व प्रश्रय की जरूरत हिमाचली युवा को है ताकि वह अपनी प्रतिस्पर्धा के फलक पर कभी शिक्षा संस्थान, कभी खेत-खलिहान, कभी स्वरोजगार के अभियान, कभी उद्यमशीलता के मैदान, कभी सांस्कृतिक आयाम या कभी निजी क्षेत्र के इम्तिहान में पूर्ण क्षमता, साहस व दक्षता से सफल होता दिखाई दे सके।

बाजार मूल्य से कम पर MX प्लेयर का अधिग्रहण करेगा अमेजन, सूत्रों का दावा- सौदा फाइनल

परिवहन विशेष न्यूज

अमेजन और एमएक्स प्लेयर ने सौदे के बारे में चुप्पी साध रखी है। लेकिन घटनाक्रम से जुड़े करीबी सूत्रों ने पुष्टि की है कि दोनों कंपनियों के बीच एक सौदे को अंतिम रूप दे दिया गया है, जिसका अंतिम भुगतान इस साल 30 जून तक होना है।

नई दिल्ली। अमेजन इंडिया ने टाइम्स इंटरनेट लिमिटेड (टीआईएल) से ओटीटी प्लेटफॉर्म एमएक्स प्लेयर के लिए पिछले अधिग्रहण मूल्य की तुलना में काफी कम भुगतान किया है। घटी हुई कीमत लगभग 45-50 मिलियन डॉलर होने की उम्मीद है। 2018 में एमएक्स प्लेयर के लिए टीआईएल की ओर से भुगतान की गई 1,000 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि से लगभग 25% कम है।

अमेजन और एमएक्स प्लेयर ने सौदे पर अब तक साध रखी है चुप्पी

हालांकि अब तक अमेजन और एमएक्स प्लेयर ने इस सौदे के बारे में चुप्पी साध रखी है। लेकिन घटनाक्रम से जुड़े करीबी सूत्रों ने पुष्टि की है कि दोनों कंपनियों के बीच एक सौदे को अंतिम रूप दे दिया गया है, जिसका अंतिम भुगतान इस साल 30 जून तक होना है।

MX प्लेयर 2022 में वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला OTT एप

data.ai की स्टेट ऑफ मोबाइल 2023 रिपोर्ट के मुताबिक, एमएक्स प्लेयर 2022 में वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ओटीटी एप था। यह भारत में सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला एप था। इस सौदे के बाद अमेजन प्राइम के उपभोक्ता बेस में चार गुना का इजाफा हो सकता है। भारत में, अमेजन के अनुमानित 2.8 करोड़ उपयोगकर्ता हैं, जबकि एमएक्स प्लेयर के लगभग 7.8 करोड़ यूजर हैं।

'सेबी को जांच के लिए अतिरिक्त छह महीने देने से जाएगा गलत संदेश', कांग्रेस महासचिव और क्या बोले

परिवहन विशेष न्यूज

सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च को सेबी को अदाणी मामले की जांच का जिम्मा सौंपा था और उससे दो महीने में रिपोर्ट मांगी थी। यह समयसीमा दो मई को खत्म हो रही है। इसके साथ ही निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए कोर्ट ने एक पैनल का भी गठन किया था।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने सोमवार को कहा है अदाणी प्रकरण की जांच के लिए सेबी को और छह महीने का समय देने से यह धारणा बनेगी कि इस मामले की जांच गंभीर रूप से नहीं की जा रही है और तथ्यों को छिपाया जा रहाचच है। शेयर बाजार की नियामक संस्था सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से जांच के लिए और छह महीने का समय मांगा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि इस पूरे प्रकरण की जांच संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी से करवाई जानी चाहिए, साथ ही अदाणी समूह पर लगे अत्यंत गंभीर आरोपों की सच्चाई का पता लगाने के लिए सेबी की त्वरित जांच भी जरूरी है।

सेबी को 2 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने सौंपा था जांच का जिम्मा, दो महीने में देनी थी रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च को सेबी को अदाणी मामले की जांच का जिम्मा सौंपा था और उससे दो महीने में रिपोर्ट मांगी थी। यह समयसीमा दो मई को खत्म हो रही है। इसके साथ ही निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए कोर्ट ने एक पैनल का भी गठन किया था। सेबी की ओर से की गई अपील से जुड़ी एक रिपोर्ट पर बोलते हुए रमेश ने कहा, सेबी को इस मामले की जांच के दौरान अदाणी मेगा स्कैम से जुड़ी कई गड़बड़ियां मिली हैं, ऐसे में इन्हें एक निर्यायक मोड़ पर पहुंचाना जरूरी है।

नियामक ने जांच पूरी करने के लिए और छह महीने का मांगा है समय

उन्होंने कहा कि जांच के लिए और छह महीने का संदेश दिया जाता है तो यह संदेश जाएगा कि जांच गंभीरतापूर्वक नहीं की जा रही है और तथ्यों को छिपाने की कोशिश हो रही है। रमेश पीएम पर हमला करते हुए बोले, ₹मोदाणी की जांच के लिए जेपीसी का गठन किया जाना चाहिए, साथ ही सेबी को भी त्वरित जांच करनी चाहिए।₹ बता दें कि सेबी ने जांच पूरा करने के लिए और छह महीने का समय मांगते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

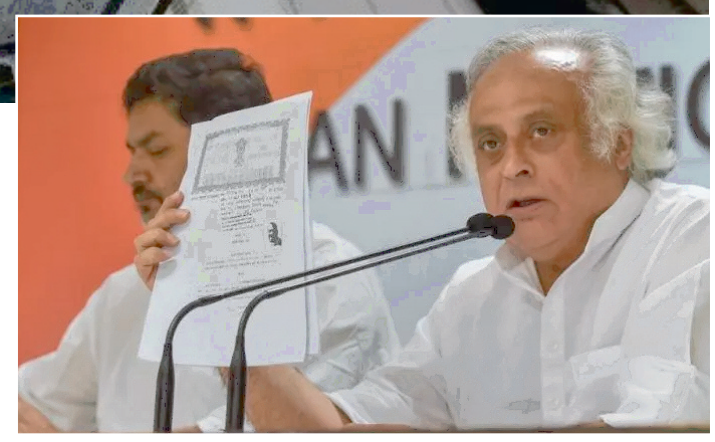

इनसाइड

अदाणी-हिंडनबर्ग विवाद के बीच एनएसई का बड़ा बयान, कहा- हमारी सभी निगरानी कार्रवाई पारदर्शी

नई दिल्ली। एनएसई की ओर से जारी बयान में कहा गया है, 'आवेदन की अवधि के साथ सटीक मापदंड सार्वजनिक डोमेन में रहे हैं और लगातार लागू किए गए हैं।' उन्होंने कहा, 'एक्सचेंजों में आम बात है कि ये नियम स्वतः लागू होते हैं और इनपर किसी भी मानवीय दखल की गुंजाइश नहीं है। साथ ही ये नियम और समीक्षा अवधि भी बाजार के लिए पूर्व-घोषित होते हैं।'

अदाणी-हिंडनबर्ग विवाद के बीच नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने अपनी निगरानी कार्रवाइयों के बारे में एक बयान जारी किया। देश के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज ने जोर देकर कहा कि सभी व्यक्तिगत शेयरों पर इसका निगरानी तंत्र पूरी तरह से पारदर्शी और मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त है। एनएसई ने रविवार को जारी एक विज्ञप्ति में कहा कि अतिरिक्त निगरानी उपायों (एएसएम) और अन्य व्यापारिक गतिविधि-आधारित विशिष्ट नियमों जैसे मूल्य बैंड, व्यापार के लिए व्यापार (टी 2 टी) और अन्य के तहत स्टॉक्स को जोड़ने और बाहर करने की प्रक्रिया उन मापदंडों पर आधारित है जो मूल्य अस्थिरता, मात्रा, बाजार पूंजीकरण, ग्राहक एकाग्रता और तरलता मापदंडों पर संचालित होते हैं। एनएसई की ओर से जारी बयान में कहा गया है, 'आवेदन की अवधि के साथ सटीक मापदंड सार्वजनिक डोमेन में रहे हैं और लगातार लागू किए गए हैं।' उन्होंने कहा, 'एक्सचेंजों में आम बात है कि ये नियम स्वतः लागू होते हैं और इनपर किसी भी मानवीय दखल की गुंजाइश नहीं है। साथ ही ये नियम और समीक्षा अवधि भी बाजार के लिए पूर्व-घोषित होते हैं।

दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज है एनएसई

दुनिया के सबसे बड़े डेरिवेटिव एक्सचेंज का यह बयान अदाणी समूह के तीन शेयरों को एएसएम तंत्र से हटाए जाने के दो दिन बाद आया है। इसमें अदाणी एंटरप्राइजेज, अडानी ग्रीन एनर्जी और नई दिल्ली टेलीविजन (एनडीटीवी) के शेयर शामिल हैं। एएसएम सेबी और एक्सचेंजों की एक पहल है जिसमें निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिभूतियों को अल्पकालिक या दीर्घकालिक ढांचे में स्थानांतरित किया जाता है। दूसरी ओर, स्टॉक एक्सचेंजों के अनुसार अदाणी समूह के दो शेयरों को सोमवार, 20 मार्च, 2023 से दीर्घकालिक अतिरिक्त निगरानी उपायों (एएसएम) के पहले चरण में रखा जाएगा। बीएसई और एनएसई ने अपने परिपत्रों में कहा कि दोनों प्रतिभूतियों को 20 मार्च से दीर्घकालिक एएसएम फ्रेमवर्क में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

उच्च अस्थिरता के कारण अदाणी समूह के शेयरों को रखा गया था एएसएम ढांचे के तहत

हालांकि एनएसई ने अपने बयान में किसी खास समूह या कंपनी के नाम का उल्लेख नहीं किया है। उच्च अस्थिरता के बीच निवेशकों की सुरक्षा के लिए एक्सचेंजों की ओर से शेयरों को अतिरिक्त निगरानी ढांचे के तहत रखा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद उच्च अस्थिरता के कारण अदाणी समूह के शेयरों को एएसएम ढांचे के तहत रखा गया है।

एक और बैंक डूबा, पहले भी कई बार खरीदा-बेचा गया; जानें कहानी अमेरिका के 14वें बड़े बैंक की

फर्स्ट रिपब्लिक बैंक को वर्षों में कई बार खरीदा और बेचा गया है। मेरिल लिंच एंड कंपनी ने 2007 में फर्स्ट रिपब्लिक का अधिग्रहण करने के लिए 1.8 बिलियन डॉलर का भुगतान किया था।

नई दिल्ली। बैंकिंग कार्यों में नाकाम रहने के बाद अमेरिका के 14वें सबसे बड़े फर्स्ट रिपब्लिक बैंक का अधिग्रहण कर लिया गया है। बैंक के अधिग्रहण के लिए बोली को जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी ने जीता। जेपी मॉर्गन फर्स्ट रिपब्लिक की संपत्ति का अधिग्रहण करेगा, जिसमें लगभग 173 बिलियन डॉलर के ऋण (लोन) और 30 बिलियन डॉलर की प्रतिभूतियां (सिक्योरिटीज), साथ ही जमा (डिपॉजिट) में 92 बिलियन डॉलर शामिल हैं।

एजेंसी ने सोमवार तड़के एक बयान में कहा कि जेपी मॉर्गन और फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्प वाणिज्यिक ऋणों (कॉमर्शियल लोन) पर नुकसान के बोझ के साथ-साथ किसी भी वसूली को साझा करने के लिए सहमत हुए। उन्होंने कहा, हमारी वित्तीय ताकत, क्षमताओं व बिजनेस मॉडल ने बोली को हासिल करने की अनुमति दी।

11 अमेरिकी बैंकों ने की थी फर्स्ट रिपब्लिक को बचाने की कोशिश

प्री मार्केट ट्रेडिंग के दौरान न्यूयॉर्क में सुबह 4:06 बजे तक फर्स्ट रिपब्लिक के शेयर 33% से अधिक टूट गए, जिससे यह इस साल की 97% की गिरावट की ओर बढने के रास्ते पर आ गया। जेपी मॉर्गन के शेयर में 3.8% की तेजी आई। 11 अमेरिकी बैंकों ने 16 मार्च को 30 अरब डॉलर की नई जमा राशि गिरवी रखकर फर्स्ट रिपब्लिक को बचाए रखने की कोशिश की थी, जिसमें जेपी मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्प, सिटीग्रुप इंक और वेल्स फार्गो एंड कंपनी भी शामिल थे। गोल्डमैन सैक्स ग्रुप इंक और मॉर्गन स्टेनली और अन्य बैंकों ने अमेरिकी नियामकों के साथ तैयार की गई योजना के हिस्से के रूप में छोटी राशि की पेशकश की थी। लेकिन यह काफी नहीं था। मार्च 2022 में 170 अरब डॉलर से ऊपर रहने वाला शेयर अप्रैल के अंत तक पांच अरब डॉलर से नीचे आ गया।

कई बार बेचा-खरीदा जा चुका फर्स्ट रिपब्लिक बैंक

फर्स्ट रिपब्लिक बैंक को वर्षों में कई बार खरीदा और बेचा गया है। मेरिल लिंच एंड कंपनी ने 2007 में फर्स्ट रिपब्लिक का अधिग्रहण करने के लिए 1.8 बिलियन डॉलर का भुगतान किया था। इसके बाद इसका स्वामित्व बैंक ऑफ अमेरिका के पास चला गया जब उसने 2009 में मेरिल लिंच को खरीदा। 2010 के मध्य में फिर जनरल अटलांटिक और कॉलोनी कैपिटल सहित निवेश फर्मों ने 1.86 बिलियन डॉलर में फर्स्ट रिपब्लिक खरीदा और फिर इसे सार्वजनिक कर दिया।

अप्रैल 2023 में जीएसटी राजस्व संग्रह 1.87 लाख करोड़ रुपये रहा, अब तक का सर्वाधिक है यह आंकड़ा

नई दिल्ली। अप्रैल 2023 में जीएसटी राजस्व संग्रह 1.87 लाख करोड़ रुपये रहा जो अब तक का कर संग्रह का सर्वाधिक आंकड़ा है। वित्त मंत्रालय की ओर से यह जानकारी दी गई है। आंकड़ों के मुताबिक जीएसटी कलेक्शन अप्रैल महीने में 1.87 लाख करोड़ रुपये रहा है जो अब तक का रिकॉर्ड है। इससे पहले मार्च 2023 में देश का जीएसटी कलेक्शन 1,60,122 करोड़ रुपये का रहा था। बीते वर्ष अप्रैल 2022 में जीएसटी कलेक्शन 1,67,540 करोड़ रुपये रहा था, यानी एक साल पहले के मुकाबले इस साल अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन में 19,495 करोड़ अधिक हुआ है। एक साल पहले की तुलना में इस वर्ष जीएसटी संग्रह में 12 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।

20 अप्रैल 2023 को हुआ सर्वाधिक जीएसटी कलेक्शन

वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में सर्वाधिक जीएसटी कलेक्शन 20 अप्रैल 2023 को हुआ। इस लिए 9.8 लाख लेनदेन के जरिए 68,228 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया गया।

अप्रैल में विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधियां चार महीने के उच्चतम स्तर पर, ये है कारण

पीएमआई के आंकड़े दर्शाते हैं कि लगातार 22वें महीने में समग्र परिचालन स्थितियों में सुधार हुआ। पीएमआई की भाषा में 50 से अधिक अंक का अर्थ है कि गतिविधियों में विस्तार हो रहा है, जबकि 50 से कम अंक संकुचन को दर्शाता है।

नई दिल्ली। भारत में विनिर्माण गतिविधियों में अप्रैल में तेजी आई और यह चार महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। एक मासिक सर्वेक्षण में सोमवार को कहा गया कि बेहतर अंतरराष्ट्रीय बिक्री और आपूर्ति-श्रृंखला की स्थिति में सुधार के कारण देश में विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधियों में इजाफा हुआ। मौसमी रूप से समायोजित एसएंडपी ग्लोबल इंडिया विनिर्माण खरीद प्रबंधन सूचकांक (पीएमआई) मार्च में 56.4 से बढ़कर अप्रैल में 57.2 हो गया। इससे पता चलता है कि इस साल अब तक इस क्षेत्र में सबसे अधिक तेजी से वृद्धि हो रही है।

लगातार 22वें महीने में समग्र परिचालन स्थितियों में हुआ सुधार

पीएमआई के आंकड़े दर्शाते हैं कि लगातार 22वें महीने में समग्र परिचालन स्थितियों में सुधार हुआ। पीएमआई की भाषा में 50 से अधिक अंक का अर्थ है कि गतिविधियों में विस्तार हो रहा है, जबकि 50 से कम अंक संकुचन को दर्शाता है।

कंपनियों को मूल्य दबाव कम रहने का मिला फायदा

एसएंडपी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस में अर्थशास्त्र की संयुक्त निदेशक पोलियाना डी लीमा ने कहा, 'नए ऑर्डर में एक मजबूती और उत्पादन वृद्धि अप्रैल में भी जारी रही।' कंपनियों को मूल्य दबाव अपेक्षाकृत रूप से कम रहने, बेहतर अंतरराष्ट्रीय बिक्री और आपूर्ति-श्रृंखला में सुधार से भी फायदा हुआ।

माल उत्पादकों को दिए गए नए ऑर्डर पिछले दिसंबर के बाद सबसे तेज गति से बढ़े हैं। बाजार की अनुकूल परिस्थितियों, अच्छी मांग और प्रचार से भी समर्थन मिला। विनिर्माताओं ने अप्रैल में उच्च परिचालन लागत का संकेत दिया है। इसके अलावा, बाजार में सकारात्मक भावना का समग्र स्तर भी मार्च से बढ़ा है।

क्या टूटेगा बीएसएफ को नियमित DG न मिलने का रिकार्ड?

दर्जनों IPS और कैडर अफसर होने पर भी किसी को अवसर नहीं

पिछले दिनों बीएसएफ के पूर्व डीजी एवं पुलिस सुधारों के लिए अथक प्रयास करने वाले प्रकाश सिंह ने बीएसएफ में स्थायी डीजी न होने को लेकर नाराजगी जताई थी। उन्होंने अपने एक ट्वीट में लिखा था कि बीएसएफ में कई माह से कोई नियमित डीजी नहीं है। यह बहुत निराशाजनक है और बल की प्रशासनिक दक्षता के लिए ठीक नहीं है...

नई दिल्ली। जब देश की सबसे बड़ी 'बॉर्डर गार्ड फोर्स' 'बीएसएफ' को अभी तक स्थायी डीजी नहीं मिल सका है। ये पद पहली जनवरी से रिक्त है। सीआरपीएफ डीजी डॉ. एसएल थाउसेन, बीएसएफ डीजी का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे हैं। इससे पहले 2020 में 150 से ज्यादा दिन तक बीएसएफ को अपने नियमित डीजी के लिए इंतजार करना पड़ा था। बल के मौजूदा और रिटायर्ड अफसर कह रहे हैं, इस बार देखने वाली बात यह है कि पुराना रिकार्ड कायम रहता है या टूट जाएगा। केंद्र में डीजी या इसके समकक्ष पद के लिए मनोनयन 'एंपेनल्ड' सूची में दर्जनभर से ज्यादा आईपीएस अधिकारी मौजूद हैं, लेकिन उनमें से सरकार को कोई पसंद नहीं आ रहा। दूसरी तरफ बीएसएफ में 35 साल या उससे अधिक समय तक सेवा दे चुके अनुभवी कैडर अधिकारी हैं, मगर केंद्र सरकार उन्हें अस्थायी डीजी की जिम्मेदारी देने को भी तैयार नहीं है।

मनोनयन सूची में पर्याप्त अफसर, लेकिन पसंद नहीं

केंद्र सरकार में डीजी या इसके समकक्ष पद ग्रहण करने योग्य आईपीएस अधिकारियों की मनोनयन 'एंपेनल्ड' सूची को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने गत दस फरवरी को मंजूरी प्रदान की थी। इसमें 1988 बैच से लेकर 1990 बैच तक के 20 आईपीएस का नाम शामिल था। इससे पहले 11 जुलाई 2022 को भी 1989 बैच के 14 आईपीएस अधिकारियों को उक्त सूची में शामिल किए जाने को मंजूरी दी गई थी। इसके बावजूद केंद्र सरकार में बीएसएफ डीजी के लिए कोई उपयुक्त आईपीएस अधिकारी नहीं मिल रहा। बल के गठन के बाद दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि इतनी लंबी अवधि तक बीएसएफ को स्थायी डीजी नहीं मिल सका। 31 दिसंबर 2022 को पंकज कुमार सिंह रिटायर हुए थे, तभी से सीआरपीएफ डीजी डॉ. एसएल थाउसेन, इस पद का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे हैं।

पूर्व आईपीएस प्रकाश सिंह ने उठाया था सवाल

पिछले दिनों बीएसएफ के पूर्व डीजी एवं पुलिस सुधारों के लिए अथक प्रयास करने वाले प्रकाश सिंह ने बीएसएफ में स्थायी डीजी न होने को लेकर नाराजगी जताई थी। उन्होंने अपने एक ट्वीट में लिखा था कि बीएसएफ में कई माह से कोई नियमित डीजी नहीं है। यह बहुत निराशाजनक है और बल की प्रशासनिक दक्षता के लिए ठीक नहीं है। फोर्स के मनोबल के लिए यह बुरा है। बीएसएफ के रिटायर्ड कैडर अधिकारी बताते हैं कि सरकार केवल आईपीएस को ही डीजी पद पर बैठाती है। कम से कम जब इस पद के लिए कोई नियमित डीजी नहीं मिल रहा हो, तो उस वक्त कैडर अधिकारी को बल की कमान सौंपी जा सकती है। बता दें कि प्रकाश सिंह, पूर्व डीजी पंकज कुमार सिंह के बेटे हैं।

काबिल अफ़सरों का टूट रहा मनोबल

इस पद के लिए योग्य अधिकारियों का कहना है, बीएसएफ डीजी जैसे अहम पद को लंबे समय तक खाली रखना ठीक नहीं है। इससे उन अफसरों का मनोबल टूट जाता है, जो इस पद के काबिल हैं। सरकार, उन्हें जिम्मेदारी देने से क्यों बच रही है। इससे पहले भी एक ही आईपीएस को चार-पांच बलों का कार्यभार दिया जाता रहा है। सरकार का यह कदम, समकक्ष अफसरों की मानसिक पीड़ा को बढ़ाता है। साल 2018 में एसएस देसवाल को आईटीबीपी का डीजी बनाया गया। उनके पास एसएसबी का अतिरिक्त प्रभार भी रहा। उन्हें सीआरपीएफ डीजी का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। इसके बाद बीएसएफ के डीजी का पद भी उन्हें मिल गया। कुछ समय बाद राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) के डीजी के रूप में भी उन्हें तैनात कर दिया गया। केंद्र में डीजी या उसके समकक्ष आईपीएस अधिकारी होने के बाद एक ही डीजी को इतने बलों का प्रमुख बना दिया जाता है। जब यह बात पहले से ही मालूम होती है कि कौन सा अधिकारी कब रिटायर होगा, तो सरकार के पास नए अधिकारी के चयन के लिए पर्याप्त समय रहता है।

रिटायरमेंट के अगले ही दिन नए डीजी आने का चलन

केएफ रुस्तमजी ने 21 जुलाई 1965 को बीएसएफ के पहले महानिदेशक का कार्यभार संभाला था। वे 30 सितंबर 1974 तक बल प्रमुख रहे। उनके बाद अश्वनी कुमार ने एक अक्तूबर 1974 को डीजी का पदभार ग्रहण किया। वे 31 दिसंबर 1978 तक रहे। श्रवण टंडन ने 1 जनवरी 1979 को बीएसएफ की कमान संभाली और 30 नवंबर 1980 तक बने रहे। उनके बाद के. राममूर्ति ने एक दिसंबर 1980 को डीजी का पदभार ग्रहण किया। वे 31 अगस्त 1982 तक इस पद पर रहे। बीरबल नाथ ने 02 अक्तूबर 1982 से 30 सितंबर 1984 तक डीजी का पद संभाला। एमसी मिश्रा, एक अक्तूबर 1984 से लेकर 31 जुलाई 1987 तक डीजी के पद पर बने रहे। एचपी भटनागर ने एक अगस्त 1987 को डीजी की कमान संभाली और 31 जुलाई 1991 तक इस पद बने रहे। टी. अनंथाचारी ने एक अगस्त 1991 को बीएसएफ डीजी का कार्यभार संभाला। वे 31 मई 1993 तक इस पद पर रहे।

प्रकाश सिंह ने संभाली थी बीएसएफ डीजी की कमान

प्रकाश सिंह ने 09 जून 1993 को डीजी की कमान संभाली और वे 31 जनवरी 1994 तक बने रहे। उनके बाद डीके आर्य को एक फरवरी 1994 को बल प्रमुख बनाया गया। उन्होंने 04 दिसंबर 1995 तक इस अपनी सेवाएं दी। अरुण भगत को चार दिसंबर 1995 को बल का कार्यभार सौंपा गया। वे एक अक्तूबर 1996 तक इस पद पर बने रहे। एके टंडन को एक अक्तूबर 1996 को बल प्रमुख बनाया गया। उन्होंने 4 दिसंबर 1997 तक अपनी सेवाएं दी। उनके बाद ईएन राममोहन ने 4 दिसंबर 1997 को बल की कमान संभाली और वे 30 नवंबर 2000 तक इस पद पर बने रहे। गुरबचन सिंह जगत को 30 नवंबर 2000 को बल की कमान सौंपी गई। वे 30 जून 2002 तक डीजी बने रहे। अजय राज शर्मा ने एक जुलाई 2002 को डीजी पद संभाला और 31 दिसंबर 2004 तक इस पद पर बने रहे। आरएस मूशाहरे ने दस जनवरी 2005 को बल की कमान संभाली और 27 फरवरी 2006 तक बने रहे। एके मित्रा को 27 फरवरी 2006 को बल की कमान सौंपी गई। उन्होंने 30 सितंबर 2008 तक इस पद पर कार्य किया। एमएल कौमावत ने 01 अक्तूबर 2008 से लेकर 31 जुलाई 2009 तक इस पद पर कार्य किया। रमन श्रीवास्तव ने एक अगस्त 2009 को बल प्रमुख का कार्यभार संभाला। वे 31 अक्तूबर 2011 तक इस पद पर बने रहे।

एत्मादपुर में संस्कार की पाठशाला लगाई गई : डॉ एमपी सिंह

परिवहन विशेष ब्यूरो

एत्मादपुर। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष में अखिल भारतीय मानव कल्याण ट्रस्ट ने एत्मादपुर में संस्कार की पाठशाला लगाई जिसमें देश के सुप्रसिद्ध शिक्षाविद समाजशास्त्री दार्शनिक प्रोफ़ेसर एमपी सिंह ने कहा कि जो विद्यार्थी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पृथ्वी माता को नमन करते हैं और अपने माता-पिता तथा बड़ों की चरण वंदना करके अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं वह उत्तम व्यक्तित्व के धनी होते हैं जो विद्यार्थी आज का काम कल पर नहीं छोड़ते हैं और सभी से विनम्रता पूर्वक बातें करते हैं अपने शब्दों में अश्लीलता और असभ्यता नहीं लाते हैं चोरी नहीं करते हैं झूठ नहीं बोलते हैं वह एक दिन घर और परिवार का गौरव बनते हैं डॉ एमपी सिंह ने कहा कि बच्चा जो बनना चाहे वह बन सकता है यदि उसका लक्ष्य निर्धारित है और उसको प्राप्त करने के लिए सतत सही दिशा में प्रयत्न कर रहा है इसलिए हमें आजकल सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम लिंकडइन व्हाट्सएप स्नैपचैट आदि से दूर रहना चाहिए क्योंकि इस सर्वर क्राइम की दुनिया में अनेकों बच्चे शोषण का शिकार हो चुके हैं तथा सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों की पालना करनी चाहिए सड़क पर यातायात के नियमों की पालना करके सड़क दुर्घटना को कम किया जा सकता है इस अवसर पर अंजू सुनीता बंदना काजल वर्षा सुजाता अनीता बबीता आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे और पर्यावरण का पाठ पढ़ाते हुए पेड़ पौधे भी लगाएं ताकि सभी को शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके और कोरोना जैसी महामारी से बच सके तथा सभी विद्यार्थियों ने संकल्प लिया कि हम सभी एक-एक पौधा अपने घर के आस-पास अवश्य लगाएंगे और उसकी देखरेख भी करेंगे तथा अन्य लोगों को पौधा लगाने के लिए जागरूक भी करेंगे।

पुलिस विभाग में लंबी सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए दो पुलिस कर्मचारियों को विदाई दी गई

रतलाम उपेंद्रपाटोदिया/ पुलिस महकमे के सहायक उपनिरीक्षक कैलाश चन्द्र यादव एवं कार्यवाहक प्रधान आरक्षक विजेन्द्र भंडारी द्वारा सेवानिवृत्ती की आयु पूर्ण करने पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में विदाई सामारोह का अयोजन किया गया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक रतलाम सिद्धार्थ बहुगुणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील पाटीदार, रक्षित निरीक्षक खिलावन सिंह कंवर ने दोनो पुलिसकर्मियों की सेवा की सराहना करते हुए उनके भावी जीवन की शुभकामनाएं दी। पुलिस अधीक्षक ने पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह देकर सेवानिवृत्ति की बधाई दी। साथ ही परिवार की जानकारी लेते हुए अच्छे स्वास्थ्य एवं आगामी जीवन की शुभकामना भी दी गई।

विदाई समारोह के अवसर पर पुलिस अधीक्षक जिला रतलाम सिद्धार्थ बहुगुणा, अतिरिक्ति पुलिस अधीक्षक सुनील पाटीदार, रक्षित निरीक्षक खिलावन सिंह कंवर एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा।

पुलिस अधिकारियो एंव कर्मचारियो के बच्चो के लिये पुलिस लाईन रतलाम मे किया गया समर केम्प का शुभारंभ

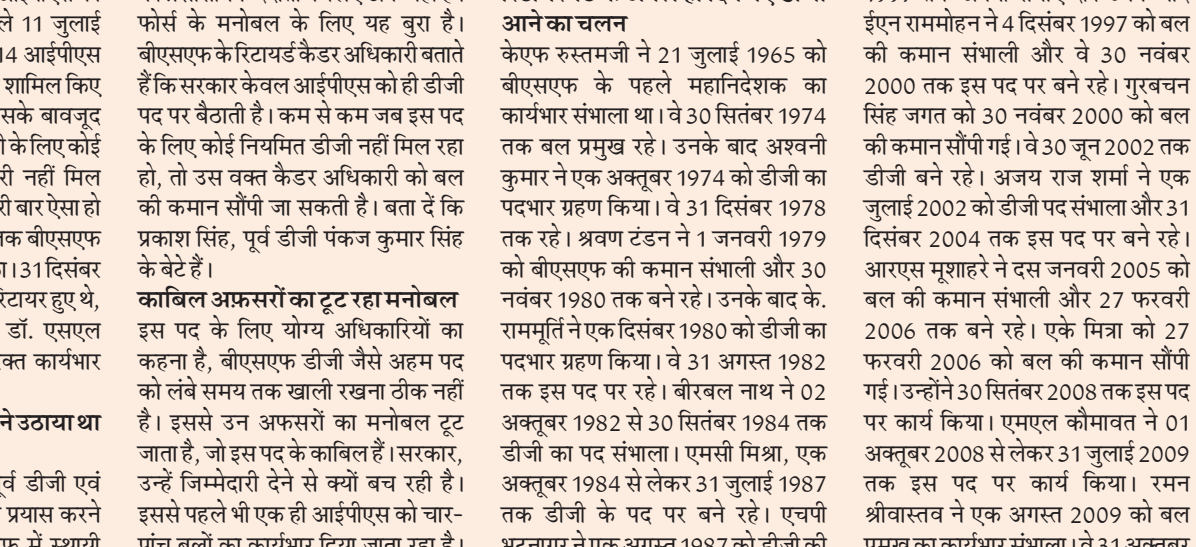

ब्यूरो चीफ उपेंद्र पाटोदिया

रतलाम। पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रदेश के प्रत्येक जिले मे पुलिस अधिकारीयो एवं कर्मचारियो के बच्चो के लिये समर केम्प आयोजित किये जाने हेतु निर्देश प्राप्त हुए। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार रतलाम जिले में पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा के निर्देशन में आज दिनांक 01.05.2023 को प्रातः 07.00 बजे पुलिस लाईन रतलाम के परेड ग्राउण्ड में 30 दिवसीय समर केंम्प का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पाटीदार, डीएसपी ट्रॉफिक अनिल राय, रक्षित निरीक्षक खिलावन सिंह कंवर, जिला क्रिड़ा अधिकारी रुबिका दिवान भी उपस्थित थे। कार्यक्रम मे जिले के पुलिस अधिकारियो एवं कर्मचारियो के 128 बच्चो द्वारा समर केम्प हेतु रजिस्ट्रेशन कराया गया है। एक माह तक चलने वाले समर केम्प में बच्चो के सर्वांगिण विकास हेतु लिये विभिन्न खेल एवं गतिविधियो को शामिल किया गया है जिसमे डांस, योगा, जूडो, क्रिकेट, वालीबाल, टेबल टेनिस, बेडमिंटन, कबड्डी, एथलेटिक्स, फुटबाल, आर्ट एण्ड क्राफ्ट, मेंहदी डिजाईन,

ब्युटीशियन, पेंटिंग आदि। प्रत्येक गतिविधियो के लिये प्रशिक्षको द्वारा सहयोग भी प्रदान किया जा रहा है जिसमे जितेन्द्र धुलिया (खेल विभाग), अमित सिंह, ममता सिंह, राशीद खान, निर्मला डामोर, जसमित कौर, पूजा सिंह, प्रीति राठौर, योगेश टांक, मिनाक्षी सिंह, दुर्गा डामोर एवं दुर्गाशंकर द्वारा बच्चो को प्रशिक्षण प्रदान किया जावेगा।

थाना स्टेशन रोड रतलाम पुलिस की बडी कार्यवाही 30 जुआरियों को जुआ खेलते पकड़ा एवं जप्त किए 2 लाख 57 हजार 220 रुपये, ताश की 10 गड्डीया व 31 मोबाईल

रतलाम। पुलिस अधीक्षक रतलाम सिध्दार्थ बहुगुणा द्वारा जिले के समस्त थाना प्रभारियो को जुए सट्टे पर प्रभावी कार्यवाही कर अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया है। इसी तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनिल पाटीदार व नगर पुलिस अधीक्षक हेमन्त चौहान के मार्गदर्शन में आज दिनांक 30.04.2023 को थाना प्रभारी स्टेशन रोड़ किशोर पाटनवाला के नेतृत्व में थाना स्टेशन रोड की टीम द्वारा जुआरियों के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही की गई है।

थाना स्टेशन रोड रतलाम की पुलिस टीम को मुखबीर सूचना मिली की प्रताप नगर क्षेत्र में डी-1, प्रताप नगर स्वप्नील सिंह के तीन मंजीला मकान में तीसरी मंजील पर एक बडा जुआ चल रहा है जिसमें काफी लोग बेठकर जुआ खेल रहे है तथा मकान मालिक उन्हे अपने मकान में बिठवाकर जुआ खिलवा रहा है। सूचना पर स्टेशन रोड पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुखबिर के बताए अनुसार दबीश दी गई जहा मौके पर बहुसंख्या में लोग इकट्ठा होकर जुआ खेलते मिले जिनमें जुआ जितेन्द्र सिह, गणपत बागरी, विनोद लोहार, गोपाल राठौर, राजा खान, अब्दुल अजीज, अबरार हुसैन, असपाक खान, रईस कुरैशी, दिनेश सिलावट, रुस्तम खोखर, अमजद मेवाती, शेरा मेवाती, सलीम बक्श, सलीम शाह, नटवर मेवाडा, पप्पन खा, जावेद खा आमीन खान, रमेश धाकड, हिम्मत कुमावत, मोहम्मद लई शेख, महिपाल सिह, असरफ हुसैन, अजहर खान, संजु कुमार, विजय राठौर, शाकीर अंसारी, शानु शाह, इरफान हूसैन जुआ खेल रहे थे। जिन्हे पकड़कर मौके पर से कुल जुआ राशि 2 लाख 57 हजार 220 रुपये व 10 ताश की गड्डी एवं 31 मोबाईल जप्त कर सभी जुआरियों के विरुध्द धारा ¾ जुआ अधिनियम में के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।जप्त मशरूका— कुल जुआ राशि 2 लाख 57 हजार 220 रुपये, 10 ताश की गड्डी, 31 मोबाईल।सराहनीय भूमिका -- निरीक्षक किशोर पाटनवाला थाना प्रभारी थाना स्टेशन रोड रतलाम, उप.निरी. सचिन डावर, स.उ.नि. एम.आई. खान, प्रआर. 344 मनीष यादव, प्रआर. 77 नरेश बाबु, प्रआर. 126 दिलीप देसाई, प्रआर. 222 धीरेन्द्र दिक्षित, प्र.आर.186 जितेन्द्रसिंह बघेल, प्र.आर.154 शेलेन्द्रसिंह, आर. 864 राजेश बक्शी आर. 597 विजय शेखावत, आर. 217 पवन मेहता, आरक्षक 132 धर्मेन्द्र मईडा, आर. आर. 812 लोकेन्द्र सोनी, आरक्षक 906 मुकेश कुमावत, आर. 282 याकुब अली,आर. 686 पारसमल धाकड, आर. 82 ललित वर्मा, आर. 469 अजीत जाट, आर. 744 हेमराज।

पुलिस ने जुआरियों का निकाला जुलूस मुंह छुपाते नजर आए जुआरी !

ब्यूरो चीफ उपेंद्र पाटोदिया

रतलाम। सोमवार को 30 से जुआरियों का जुलूस निकालकर उन्हें एसडीएम के समक्ष पेश किया गया जहां पर जमानत पर उन्हें रिहा किया गया इन सभी जुआरियों पर जुआ एक्ट के अलावा शांति भंग करने की धारा लगाई गई है। स्टेशन रोड पुलिस ने रविवार शाम को प्रताप नगर में चलाए जा रहे जुए के एक अड्डे पर छापा मारा था और यहां जुआ खेल रहे तीस जुआरियों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने इन जुआरियों के कब्जे से ढाई लाख रुपए से अधिक नगद व मोबाइल फोन भी जब्त किए थे।एसडीएम कोर्ट तक जुआरियों को पैदल लेकर निकली पुलिसस्टेशन रोड पुलिस ने इन सभी आरोपियों पर जुआ एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज करने के साथ ही शांत भंग करने की धारा 151 दप्रसं का प्रकरण भी लगा दिया है। धारा 151 के आरोपियों को एसडीएम कोर्ट में पेश किया जाता है। पुलिस ने जुए के सभी आरोपियों को पैदल ही कलेक्टोरेट कार्यालय तक ले कर गई ताकि शहर के लोग इनका जुलूस देख सके। जुलूस की शक्ल में न्यायालय ले जाने के दौरान कई आरोपी अपना मुँह छुपाने की कोशिश करते देखे गए।

रतलाम मंडल की दो जोड़ी ट्रेनों में अतिरिक्त डिब्बों की सुविधा

रतलाम उपेंद्र पाटोदिया / ग्रीष्मकालीन की छुट्टियों के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ के मद्देनजर व यात्रियों की सुविधा के लिये ट्रेन न. 12465/12466 इंदौर-जोधपुर-इंदौर रणथंभौर एक्सप्रेस में इंदौर से 2 मई से 1 जून, 2023 तक व जोधपुर से 3 मई से 2 जून, 2023 तक एक थर्ड एसी व एक द्वितीय श्रेणी सामान्य कोच अस्थायी रूप में लगाये जायेंगे। ट्रेन न. 14802/14801 इंदौर-जोधपुर-इंदौर एक्सप्रेस में इंदौर से 4 मई से 3 जून, 2023 तक व जोधपुर से 1 मई से 31 जून, 2023 तक एक थर्ड एसी व एक द्वितीय श्रेणी सामान्य कोच अस्थायी रूप में लगाये जायेंगे।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 98117320959.
किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय में ही होगा। समाचार पत्र में प्रकाशित किये गये मसौदे के लिए लेखक स्वयं जिम्मेदार हैं। **Title Code : DELHIN28985. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023**